सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 169, नई दिल्ली, बुधवार 27 अगस्त 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सबसे कठिन काम है कार्य करने का निर्णय लेना, बाकी सब केवल दृढ़ता है...

03 सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित ट्राइब्यूनल (NGT) के आदेश को रद्द किया

06 वैज्ञानिक ग्रहों या सितारों के तापमान का निर्धारण कैसे करते हैं

08 सीमा पार से हथियारों की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़; 5 ग्लॉक पिस्तौल सहित एक गिरफ्तार

राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2025 के उपलक्ष्य में,

राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2025 के उपलक्ष्य में पीईएफआई (PEFI), युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय गौरव के लिए सवारी।

प्रयागराज से दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर और आगरा होते हुए -
24 अगस्त से 31 अगस्त तक,

अमर हॉकी आइकन मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए।

आइये विरासत के लिए आगे बढ़ें, आइये भारत के लिए आगे बढ़ें।

हम 31 अगस्त को सुबह 7:30 बजे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, इंडिया गेट पर ग्रैंड फिनाले के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं... हमसे जुड़ें

आत्मनिर्भर भारत और वोकल फार लोकल के तहत
शिल्पी सम्मेलन एवं विरासत उत्सव 2025 बुनकरों और कारीगरों की प्रदर्शनी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सीआर पार्क पुलिस स्टेशन के पास अपराजिता महिला समिति में सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक, 30 अगस्त, 2025 तक चल रही है।

यह प्रतिष्ठित कार्यक्रम सांस्कृतिक विरासत, स्थायी आजीविका, सामाजिक प्रभाव पहल, कलात्मक अभिव्यक्ति, ग्रामीण-शहरी एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, जिसका विषय है **'गांव को जोड़े शहर के साथ, विकास हो हाथो हाथ'।**

इस महोत्सव का उद्देश्य सशक्तिकरण, उद्यमिता, सतत विकास और आजीविका का सृजन, हमारी सदियों पुरानी परंपराओं, विरासत और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन, कौशल विकास, प्रशिक्षण, रोज़गार के अवसर और आर्थिक वृद्धि के माध्यम से मूल्यों और शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना है।

महिला मोक्षा महिला संगठन, कारीगरों और बुनकरों का अपना संगठन, **इनके माध्यम से आप सीधे प्राप्त कर सकते हैं हाथ के बने सामान कारीगरों और बुनकरों से**

महिला मोक्षा नाम से महिला संगठन चलाते हैं, जो पूरे भारत के कारीगरों और बुनकरों के साथ मिलकर काम करता है और उन्हें स्थायी आजीविका के लिए प्रोत्साहित करता है।

हम एक स्थायी मंच बनाने और एक मजबूत बाजार संपर्क प्रदान करने के लिए आपकी मदद और समर्थन चाहते हैं, जो बुनकरों, कारीगरों, महिला उद्यमियों के सभी वर्गों के लिए एक मजबूत आधार होगा, जो भारतीय समाज के पिछड़े वर्ग और हाशिए पर रहने वाले वर्ग से संबंधित हैं, हम **भारत के बुनकरों और कारीगरों से स्वदेशी उत्पादों की खरीद की मांग करते हैं, जिन्होंने 2020 के बाद से महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आजीविका खो दी है।**

हम भारत भर में जूट, बांस, शीतल पाटी, घास की चटाई और कुछ पारंपरिक विशेष हस्तनिर्मित जनजातीय हस्तशिल्प उत्पादों, साथ ही जातीय हथकरघा उत्पादों का उत्पादन और खरीद-बेचफिर से शुरू करना चाहते हैं।

आत्मनिर्भर भारत और वोकल फ़ॉर लोकल के उद्देश्य के लिए आपके समर्थन, सहायता, संरक्षण और उदारता के प्रति आपसे अनुरोध है। ग्रामीण भारत में रहने वाले परिवारों में से अधिकांश महिला कारीगर, बुनकर और युवा घोर गरीबी और दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। इन परिवारों की सहायता के लिए आपका समर्थन और संरक्षण की कामना करता हूं।

महिला मोक्षा बुनकरों और कारीगरों को सतत विकास और आजीविका प्रदान करने के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी रचनात्मकता की कहानियों को साझा करना चाहता है, पूरे भारत में वोकल फॉर लोकल स्टोर्स की स्थापना करना चाहता है, जिससे भारत के युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों। महिला मोक्ष कारीगरों और बुनकर समुदाय से जुड़े कुछ सौ हिंदू परिवारों के लिए हुनर हाट की तर्ज पर वोकल फॉर लोकल हाट का आयोजन करना चाहता है। हुनर हाट, जो मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए था, ने हमारे हिंदू परिवारों को रोजगार के अवसर पैदा करने में किसी भी तरह से मदद नहीं की, इसलिए हम पूरे भारत में हिंदू बुनकरों और कारीगरों द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खुदरा स्टोर स्थापित करना चाहते हैं।

विकास का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है समग्र शिक्षा, जिसे हम व्यवस्थित रूप से युवा और वृद्ध सभी के मन में स्थापित करना चाहते हैं। इस संबंध में विचारणीय कुछ बिंदु इस प्रकार हैं:

1. श्रीमद भागवत गीता चैटिंग इन स्कूल्स.
2. सभी स्कूलों में निर्देशित ध्यान अनिवार्य किया गया।
3. धर्मग्रंथों से पढ़ना.
4. शैक्षणिक संस्थानों में कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण।
5. छोटे बच्चों में अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालना।
6. भारत भर के प्रत्येक जिले में पुस्तकालयों का निर्माण।
7. नैतिक मूल्यों का संचार, मूल्य शिक्षा, नैतिक जीवन, सामाजिक संबंध निर्माण, शांतिपूर्ण अस्तित्व।
8. युवा पीढ़ी को अधिक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्कूलों में समय-समय पर पुस्तक मेले और प्रदर्शनी आयोजित करना।
9. शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए पोषण, भोजन, योग, करियर, माइंडफुलनेस जैसे विविध विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

मानवता और मानवीय गरिमा के लिए कृप्या अपनी दयालुता और उदारता का हाथ बढ़ाएँ। एकत्रित धनराशि का उपयोग स्थायी आजीविका प्रदान करने, कौशल विकास केंद्रों के निर्माण, परिवारों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए शुल्क प्रदान करने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से भारतीय परंपरा, संस्कृति और विरासत को बनाए रखने के लिए कार्यात्मक बाजार संपर्क के एक मजबूत, विश्वसनीय और स्थायी आजीविका मॉडल के निर्माण के लिए किया जाएगा।

हम बुनकरों, कारीगरों, कृषि क्षेत्र, एफपीओ और महिला उद्यमियों के माध्यम से कृषि उत्पादों के लिए एक सहकारी संगठन शुरू करना चाहते हैं, अन्य कार्यक्षेत्र जिनके लिए हम काम करना चाहते हैं वे हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन, खुदरा स्टोर, प्रदर्शनी, बाजार संपर्क पहल, निर्यात, कॉर्पोरेट उपहार, शिल्प कैफे, प्रशिक्षण और कौशल विकास।

कृप्या हमारे कारीगरों, हमारी पहल, परंपरा, संस्कृति, भारत के हमारे अपने बुनकरों को बचाने में हमारी मदद करें। हमारा संगठन मानवता और मानव गरिमा के लिए काम करने वाला एक महिला संगठन है। हम इन हाशिए पर पड़े वर्गों के कल्याण के लिए आपका समर्थन चाहते हैं तथा भारत की महिलाओं और युवाओं का समर्थन करते हैं।

इस पहल को शुरू करने के लिए जन प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और धन की आवश्यकता है। हम पूरी विनम्रता के साथ, विकसित भारत के लिए आपकी सहायता, समर्थन, दया, सहयोग, विचार, सहभागिता, मार्गदर्शन, सलाह और संरक्षण की अपेक्षा करते हैं।

रक्षा द सेवियर की ओर से प्रस्तुत
गरबा महोत्सव में विशेष अपील
हमारी रक्षा द सेवियर की ओर से
रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव में आने वाले सभी लोगों से विनम्र निवेदन है—
इस नवरात्रि एक सेवा ड्राइव चलाई जा रही है

आप अपने घर से लाएँ और दान करें :
- पुराने कपड़े
- पुराने कंबल
- पुराने जूते-चप्पल
- बच्चों के लिए बैग
- किताबें

आपका छोटा-सा योगदान किसी ज़रूरतमंद के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है

स्थान :
रक्षा गरबा डांडिया एवं दुर्गा पूजा महोत्सव
रामलीला मैदान के सामने, आरटीओ ऑथोरिटी के पास
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

विशेष सूचना
नवरात्रि में मातारानी की खंडित मूर्तियाँ, टूटे हुए फ़ोटो, पुरानी चुनरियाँ और नवरात्रि में बोए गए जवारों का विसर्जन
- दशहरे के दूसरे दिन
- दिनांक : 3 अक्टूबर की सुबह
- स्थान : रक्षा नवरात्रि गरबा एवं दुर्गा पूजा ग्राउंड

स्थान विवरण :
रामलीला मैदान के सामने,
आरटीओ ऑथोरिटी के पास,
सेक्टर 10 डीडीए ग्राउंड, नई दिल्ली

संपर्क सूत्र :
इंदु राजपूत – 9210210071
सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि इस पावन विसर्जन में सहभागी बनें।

महिला मोक्षा संगठन द्वारा टैंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत की महासचिव पिंकी कुंडू को सम्मानित किया गया।

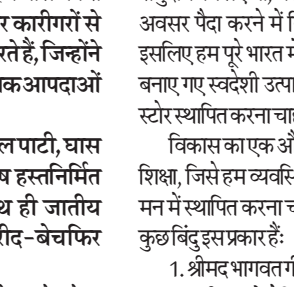

महिला मोक्षा संगठन द्वारा परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के संपादक संजय कुमार बाटला और डिजाइनर दिलीप देवतवाल को सम्मानित किया गया।

धर्मस्थला में दबे सत्य और न्याय को उजागर करना जरूरी

के एस विमला, अनुवादक : संजय पराते)

हरे-भरे जंगलों और धीमी-धीमी बहती जलधाराओं से घिरा, और चूंकि यह बरसात का मौसम है — बहते पानी का तेज़ खिंचाव, बारिश की पुकार करते मोर और तोतों की चहचहाहट; यह एक ऐसी जगह है, जो मन को प्रसन्न करती है। लेकिन यहाँ दुःख भारी है और मन पर सन्नाटा छाया हुआ है।

यह दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलटांगड़ी तहसील के पास पद्मलता का घर है। पद्मलता एक किशोरी हैं, जो लगभग चार दशक पहले 1986 में उन लोगों के अन्याय और अहंकार का शिकार हुईं थीं, जिन्होंने धर्म की आड़ में उत्पीड़न का इस्तेमाल किया था। हाल ही में, कॉ. के. प्रकाश (पार्टी राज्य सचिव), के. एस. विमला, मुनीर कटिपल्ला (पार्टी दक्षिण कन्नड़ जिला सचिव) और अन्य स्थानीय नेताओं सहित एक माकपा प्रतिनिधिमंडल ने पद्मलता के घर का दौरा किया।

पद्मलता को याद करते हुए

धर्मस्थल और उसके आस-पास की कई तथाकथित ₹अप्राकृतिक मौतों₹ में से, जिन्हें ₹अप्राकृतिक मौत₹ के नाम पर हाशिये पर धकेल दिया गया था, यह पहला मामला था। इस मौत की गूंज विधान सभा में भी सुनाई दी थी। उस समय, तत्कालीन गृह मंत्री बी. रचैया पद्मलता के घर गए थे। लेकिन, चूँकि संदिग्ध आरोपी बहुत प्रभावशाली लोग थे, इसलिए मामला आगे नहीं बढ़ा — यह राख के नीचे दबे अंगारों की तरह ही रहा।

पद्मलता कॉलेज गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। उसका अपहरण कर लिया गया था। सत्तावन दिन बाद, उसका शव नेरिया नदी के पास चट्टानों के बीच मिला। उसने जो कपड़ा पहना था और उसकी कलाई पर जो घड़ी थी, उससे उसकी पहचान पुख्ता हुई। कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि अपराधियों ने उसे हर तरह से शिकार बनाया था और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। यह कोई अकेली घटना नहीं थी — ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर देश का क़ानून या लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था।

उस समय, स्थानीय निकाय चुनावों में माकपा के सदस्य चुनाव लड़ रहे थे और उनमें से एक पद्मलता के पिता, देवानंद भी थे, जो एक किसान और माकपा नेता थे। उन पर चुनाव से हटने का दबाव था और चूंकि उन्होंने इसके आगे झुकने से इंकार कर दिया था, इसलिए उनकी बेटी की हत्या कर दी गई और संभवतः बलात्कार के बाद यह हत्या हुई थी।

यद्यपि धर्मस्थला एक धार्मिक केंद्र है, जहाँ लाखों लोग आते हैं और जिसके पास अपार भूमि, धन और संसाधन हैं, फिर भी यह ऐसी ₹अप्राकृतिक मौतों₹ के लिए उतना ही कुख्यात है। यह पूरा क्षेत्र एक नामी परिवार के चंगुल में है, जो अपनी विभिन्न अलौकिक खिताबों की आड़ में अपनी असीम सामंती-धार्मिक शक्ति का प्रदर्शन करता रहता है। जो कुछ भी उसकी नज़र में आता है — स्त्री, सोना, ज़मीन — उसे वह अपनी निजी संपत्ति मान लेता है और उसे हड़पने के लिए वे किसी भी हद तक जाकर अत्याचार करते हैं। 1960 और 70 के दशक में, जब अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों द्वारा भूमि सुधार अधिनियम के तहत काश्तकारी पंजीकरण और घोषणाएँ हो रही थीं, उसी दौरान सबसे ज़्यादा हिंसक धमकियाँ और हमले इसी क्षेत्र में हुए थे। उस समय, इस धार्मिक-सामंती शक्ति और अत्याचार का प्रकोप अपने चरम पर था। यह आज भी कई रूपों में जारी है।

उस शोकाकुल परिवार की मुखिया, पद्मलता की माँ, अपनी वाणी और स्मरण शक्ति दोनों खो चुकी हैं। लेकिन जब वह अपनी बेटी का नाम सुनती हैं, तो उनकी आँखों में अचानक आँसू आ जाते हैं। धीरे-धीरे उन्हें वह दिन याद आता है, जब उनकी बेटी गायब हुई थी। वह यह कहकर कॉलेज गई थी कि वह वापस आएगी, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। वह अपनी लड़खड़ाती आवाज़ और अवरूद्ध कंठ में कहती हैं, ₹धर्मस्थल वाले ही उसे ले गए थे। पुलिस ने कभी हमारी मदद नहीं की।₹

इतनी सारी ₹अप्राकृतिक मौतें₹ क्यों?

1980 के दशक में, माकपा ने स्थानीय सामंती ताकतों को पहला झटका दिया था। तब पार्टी ने उनके इस हठ को चुनौती दी थी कि सब कुछ उनकी निगरानी में होना चाहिए — यहाँ तक कि चुनाव के उम्मीदवारों का फैसला भी उनकी निगरानी में ही होना चाहिए। चूंकि पार्टी ने अपने फ़ैसलों के अनुसार उम्मीदवार उतारे थे, इसलिए पद्मलता के पिता को अपनी बेटी की हत्या की त्रासदी झेलनी पड़ी। इसके बाद, कई अन्य ₹अप्राकृतिक मौतों₹, हत्याओं और बलात्कारों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन हुए और जन संगठनों के नेतृत्व में ज़िला केंद्र और बेंगलुरु में मार्च, सार्वजनिक प्रदर्शन किए गए और रैलियाँ निकाली गईं।

इस दौरान कई पुराने मामले सामने आए, जैसे : ज़मीन से जुड़े एक विवाद में एक हाथी के महावत नारायण और उसकी बहन की मौत, हाई स्कूल में प्रधानाध्यापिका के पद के लिए संघर्ष करने वाली वेदवल्ली को ज़िंदा जला देना, और बाद में 2012 में सौजन्या का मामला, जिसने फिर से जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। उस समय ही, एक आरटीआई से पता चला कि ₹अप्राकृतिक मौतों₹ के 400 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए थे।

संघर्ष की तीव्रता ने सिद्धारमैया सरकार को मामला सीबीआई को सौंपने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उससे पहले, मामले की उस ₹आखिरी कड़ी₹ को, जो अंदरूनी सच्चाई उजागर करने वाला एक अहम गवाह बन सकता था, मारकर कुएँ में फेंक दिया गया। उस मामले में, प्रभावशाली संदिग्धों को बचाने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति, संतोष राव, को बलि का बकरा बनाया गया।

सीबीआई जाँच में प्रारंभिक जाँच की कई खामियाँ उजागर हुईं और अदालत ने संतोष राव को बरी कर दिया और सरकार को गंभीर चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। इसके बाद बेंगलुरु और पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए — जैसे ₹बेलटांगडी चलो₹ रैली -- लेकिन मामला वहीं रुक गया। इस बीच, और भी अन्य ₹अप्राकृतिक मौतों₹ के बारे में नए खुलासे सामने आते रहे।

सीरियल किलर₹ का मीडिया में पर्दाफ़ाश

हाल ही में समीर नाम के एक यू-ट्यूबर की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया, जिसने धर्मस्थल में तथाकथित ₹अप्राकृतिक मौतों₹ के ₹सीरियल किलर₹ का पर्दाफ़ाश करने का दावा किया था। पुलिस ने उस पर ₹अफ़वाह फैलाने₹ का मामला भी दर्ज किया। कई अन्य यू-ट्यूबर्स ने भी ऐसी ही रिपोर्ट्स प्रकाशित कीं। कुछ दिनों बाद, धर्मस्थला के सफाई विभाग में काम करने का दावा करने वाला एक गुमनाम व्यक्ति वकीलों के साथ अदालत में आया और उसने कबूल किया कि उसने कई शवों को दफनाया था, जिन्हें ₹अप्राकृतिक मौतें₹ माना गया था और अब वह अपराध बोध से ग्रस्त है। शुरुआत में, सरकार ने अपना हमेशा की तरह टालमटोल वाला रवैया अपनाया। यहाँ तक कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने भी ऐसा जताया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सोशल मीडिया के दबाव और जनाक्रोश के कारण, एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करना पड़ा।

माननीय आईपीएस अधिकारी प्रणव कुमार मोहंती के नेतृत्व में एसआईटी ने काम शुरू कर दिया है। एक हेल्पलाइन भी स्थापित की गई। इसके तुरंत बाद, एक लापता महिला अनन्या भट्ट की माँ, सुजाता भट्ट, ने एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बरामद कंकालों (यदि और जब भी मिलें) का डीएनए परीक्षण कराने का अनुरोध किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे उनकी बेटी के हैं या नहीं। हालाँकि ₹व्यक्तिगत कारणों₹ से एक सदस्य एसआईटी से हट गए हैं और एसआईटी के एक अन्य सदस्य के खिलाफ शिकायतों का मामला सामने आया है, फिर भी अब तक का काम संतोषजनक प्रतीत होता है। और अन्य लोग भी एसआईटी के पास अब शिकायत लेकर आगे आए हैं।

इस मामले का एक अन्य आयाम यह है कि धर्मस्थला मंजूनाथ-अन्नप्पा मंदिर एक हिंदू धार्मिक स्थल है, लेकिन इसकी देखरेख करने वाला हेगड़े परिवार जैन है, जिसके कारण कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि इसका नियंत्रण हिंदुओं को दिया जाना चाहिए।

मीडिया पर प्रतिबंध के आदेश

सोशल मीडिया (खासकर यू-ट्यूब चैनल) लगातार खोजी अभियान चला रहे हैं और स्थानीय सच्चाइयों को उजागर कर रहे हैं। एसआईटी ने उस गुमनाम व्यक्ति के आरोपों की भी जाँच शुरू कर दी है। हालाँकि एसआईटी ने खुदाई में किसी हड्डी या कंकाल के मिलने की सूचना नहीं दी है, लेकिन कई जानकार सूत्रों से पता चला है कि कई हड्डियाँ, कंकाल, महिलाओं के कपड़ों के टुकड़े और डेबिट कार्ड मिले हैं।

जब सीबीआई अदालत का फैसला आया, तो घटनाक्रम को दबाने के लिए, हेगड़े परिवार की ओर से कुछ लोगों ने उनका नाम उजागर करने या उनके बारे में रिपोर्ट करने पर रोक लगा दी। गंभीर आरोपों का सामना कर रहे लोगों के लिए अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के बहाने एकतरफा निषेधाज्ञा प्राप्त करना अब आम बात हो गई है। बाद में, निषेधाज्ञा के इस आदेश को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पलट दिया। फिर इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली और सर्वोच्च न्यायालय ने उसी न्यायालय से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। जब यह बताया गया कि इस तरह के निषेधाज्ञा जारी करने वाले न्यायाधीश, हेगड़े परिवार और उनके कई संगठनों की कानूनी टीम का हिस्सा थे, जो पहले वकील के रूप में काम कर चुके थे, तो उसके द्वारा मामला दूसरे न्यायाधीश को सौंप दिया गया। स्वतंत्र पत्रकारों पर भी शारीरिक हमले हुए हैं।

अब मामला फिर गरमा गया है। स्थानीय स्तर पर भय का माहौल बनाने की कोशिशें चल रही हैं। पूर्व ग्राम पंचायत सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि धर्मस्थल स्थित नेत्रवती में ₹अप्राकृतिक मृत्यु₹ के सभी पीड़ितों का अंतिम संस्कार पंचायत के नियमों के अनुसार किया गया था। चिंताजनक बात यह है कि स्थानीय पुलिस थाने में उस समय के सभी रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए हैं। निष्पक्ष जाँच की माँग करते हुए, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आधिकारिक साक्ष्य नष्ट न हों।

अगर एसआईटी की जाँच के दौरान ही इन सभी मामलों के रिकॉर्ड मिटा दिए गए हैं, तो यह ₹अदृश्य हाथों₹ की ताकत को दर्शाता है। सौजन्या मामले में भी जानबूझकर सबूत मिटाने के गंभीर आरोप लगे थे, और अब यहाँ भी यही संभव प्रतीत होता है। इसके लिए सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

आरएसएस-भाजपा की भूमिका

धर्मस्थला के मामलों को केवल ₹अप्राकृतिक मौतें₹ कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। ये ज़मीन और आजीविका के अधिकार सहित लोगों के अधिकारों से जुड़े मामले हैं। राज्य भर में चल रहे धर्मस्थला ग्रामीण विकास कार्यक्रमों -- सूक्ष्म वित्त ऋण, अत्यधिक ब्याज दरें, पुनर्भुगतान के लिए उत्पीड़न आदि -- की भी जाँच होनी चाहिए। माकपा ने माँग की है कि सभी ₹अप्राकृतिक मौतों₹ की जाँच, जिनमें पूर्व के सुप्रसिद्ध मामले (जैसे : वेदवती, पद्मलता, सौजन्या आदि मामले) भी शामिल हैं, विशेष जाँच दल (एसआईटी) को सौंपी जानी चाहिए। अगर कोई कानूनी अड़चन है, तो माकपा ने एक अलग विशेष जाँच दल (एसआईटी) की माँग की है। माकपा सामंती-धार्मिक आतंक और पुलिस, प्रशासन व अन्य राजनीतिक दलों की मिलीभगत के खिलाफ संघर्ष में सबसे आगे रही है।

दक्षिण कन्नड़ में आरएसएस का एक गुट यहां संघर्ष का हिस्सा है -- जाहिरा तौर पर न्याय के लिए, लेकिन साथ ही इसमें एक अंतर्निहित हिंदुत्ववादी मोड़ भी है, जो 'हिंदू मंदिर पर जैनों के स्वामित्व' को चुनौती दे रहा है।

यह उल्लेखनीय है कि अन्य राजनीतिक दल चुप रहे हैं। सैकड़ों अप्राकृतिक मौतों, महिलाओं के साथ बलात्कार, गरीबों की ज़मीन हड़पने, कर्ज़ों पर अत्यधिक ब्याज दरों और भुगतान न करने पर संपत्ति ज़ब्त करने के बावजूद, विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके मीडिया संस्थानों ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई है — जो आज लोकतंत्र की बदहाल हालत को दर्शाता है।

भाजपा और संघ परिवार के संगठन और उनका मीडिया (जिसमें उनके मुख्यधारा का गोदी मीडिया भी शामिल है) यह कहकर इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि ₹हिंदू धार्मिक प्रथाओं और संगठनों₹ पर हमला हो रहा है। वे जाँच के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं और जनमत को प्रभावित करने के लिए इसे कम्युनिस्ट पार्टी और केरल सरकार की ₹हिंदू-विरोधी साजिश₹ भी बता रहे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और उसके नेता आत्मसमर्पण की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं।

सीपीआई (एम) ₹धर्मस्थला में पीड़ितों के साथ दफनाए गए सत्य और न्याय₹ को उजागर होने तक अंत तक लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

(लेखिका माकपा कार्यकर्ता हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं।)

गणेश चतुर्थी आज

सनातन धर्म में गणेश महोत्सव का विशेष महत्व है। यह त्योहार महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के कई राज्यों और विदेश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। खासकर, महाराष्ट्र में गणेश पूजा को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिलता है। हर घर में प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से गणपति बप्पा की पूजा की जाती है। धार्मिक मत है कि भगवान गणेश की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। सनातन धर्म में भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है।

कब से शुरू होता है गणेश महोत्सव?

===========================

हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गणेश महोत्सव शुरू होता है। वहीं, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। दस दिवसीय गणेश महोत्सव देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है।

कब मनाया जाएगा चौरचन?

======================

हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर चौरचन मनाया जाता है। यह पर्व बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। मैथिली पंचांग के अनुसार, 26 अगस्त को चंद्र देव को समर्पित चौरचन मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर संध्याकाल में चंद्र देव की पूजा की जाती है।

कब से शुरू होगा गणेश महोत्सव?

=========================

सनातन धर्म में निशा काल पूजा को छोड़कर अन्य सभी पूजा में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए गणेश चतुर्थी पर उदया तिथि से गणना की जाएगी। इस प्रकार 27 अगस्त से गणेश महोत्सव की शुरुआत होगी। वहीं, 06 सितंबर को गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा।

स्थापना मुहूर्त

================

ज्योतिषियों के मुताबिक गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना के लिए 27 अगस्त को सुबह 11 बजकर 05 मिनट से लेकर दोपहर 01 बजकर 40 मिनट तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। आप इस अवधि में गणपति जी की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं।

गणेश चतुर्थी दुर्लभ संयोग

====================

इस बार गणेश चतुर्थी पर प्रीति, सर्वार्थ सिद्धि, रवि के साथ इंद्र-ब्रह्म योग का संयोग बना रहेगा। वहीं कर्क में बुध और शुक्र के होने से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर बुधवार का महासंयोग तिथि की महत्ता को गई गुना बढ़ा रहा है।

कैसे करें गणपति की स्थापना और पूजा?

=============================

प्रातःकाल स्नान के बाद सबसे पहले व्रत और पूजा का संकल्प लें।

घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं।

गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें, उन पर गंगाजल छिड़कें और उनका अभिषेक करें।

गणपति को सिंदूर, दूर्वा (21 पत्तियाँ), लाल फूल, मोदक, लड्डू, नारियल, गन्ना, फल और नैवेद्य अर्पित करें।

गणेश चालीसा, अथर्वशीर्ष या फिर गणपति स्तोत्र का पाठ करें।

पूजा के अंत में घंटा, शंख और मंजीरे के साथ गणेश जी की आरती करें।

यह पूजा प्रक्रिया सायंकाल के समय भी दोहराई जाती है, ताकि दिन भर गणेशजी की उपासना बनी रहे। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन और दान देकर फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें।

गणेश चतुर्थी का महत्व

====================

हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन दोपहर के समय हुआ था, इसीलिए इस तिथि और समय को अत्यंत शुभ माना जाता है। वे प्रथम पूज्य, बुद्धि के दाता और विघ्नों को हरने वाले देवता हैं। कोई भी धार्मिक कार्य, विवाह, यात्रा या नया कार्य बिना गणपति पूजन के शुरू नहीं किया जाता। इस दिन का भक्तों को सालभर इंतज़ार रहता है क्योंकि यह दिन उनके लिए उत्सव, भक्ति और आनंद से भरा होता है।

त्योहारों के मद्देनज़र त्रैमासिक परीक्षा स्थगित करने की मांग, विश्व हिन्दू राष्ट्र परिषद ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

ईसाई मिशनरियों द्वारा सुनियोजित रूप से हिन्दू एवं जैन पर्वों के समय परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जो हमारी आस्थाओं के विरुद्ध है। - अविनाश राणा

आगरा, विशेष संवाददाता पंकज जैन। विश्व हिन्दू राष्ट्र परिषद ने आज जिलाधिकारी आगरा को एक ज्ञापन सौंपकर आगामी 26 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक प्रस्तावित त्रैमासिक परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है। परिषद का कहना है कि इस अवधि में हिन्दू और जैन समुदायों के कई महत्वपूर्ण पर्व जैसे गणेश चतुर्थी, अनन्त चतुर्दशी, ओणम और डोल ग्यारस मनाए जाते हैं, जिनमें विद्यार्थियों और परिवारों की व्यापक सहभागिता रहती है। इस कारण इस दौरान त्रैमासिक परीक्षा ना कराई जाए।

ज्ञापन में परिषद ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि इन पर्वों की सामाजिक और धार्मिक महत्ता को देखते हुए परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन किया जाए, ताकि छात्र-छात्राएं बिना मानसिक दबाव के अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर सकें।

परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक अविनाश राणा ने कहा कि, ₹ईसाई मिशनरियों द्वारा सुनियोजित रूप से हिन्दू एवं जैन पर्वों के समय परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जो हमारी आस्थाओं के विरुद्ध है। उन्होंने जिला अधिकारी आगरा से आग्रह किया कि इन त्रैमासिक परीक्षाओं को आगे की तिथि में कराया जाए जिससे इन प्रमुख पर्वों को हम बिना किसी चिंता से धूमधाम से मना सके जो हम सभी सैकड़ों वर्षों से मनाते आ रहे हैं। यदि मौसम या अन्य कारणों से परीक्षा तिथियों में बदलाव संभव है, तो धार्मिक पर्वों के अवसर पर यह मांग भी न्यायोचित है।"

परिषद के प्रदेश अध्यक्ष पंडित राजकुमार त्रिवेदी ने भी आरोप लगाया कि ₹हर बार जानबूझकर हमारे धार्मिक पर्वों पर ही परीक्षाएं रखी जाती हैं। यह हमारी संस्कृति और परंपराओं को कमजोर करने की एक साज़िश है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब ज्यादा सर्दी ज्यादा गर्मी और अधिक वारिस में परीक्षा आगे बढ़ा दी जाती है तो हमारे प्रमुख पर्वों क्यों नहीं?"

इसके साथ ही परिषद के प्रदेश संरक्षक दीपकवीर सिंह चौहान एवं प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा ने जिला अधिकारी से यह मांग की कि पर्वों के दौरान मांस एवं मदिरा की दुकानों को बंद रखने का प्रशासनिक आदेश जारी किया जाए, जिससे सामाजिक सौहार्द बना रहे और धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

ज्ञापन सौंपने वालों में कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे, जिनमें राष्ट्रीय संरक्षक अविनाश राणा, प्रदेश अध्यक्ष पंडित राजकुमार त्रिवेदी, प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा, प्रदेश संरक्षक दीपकवीर सिंह चौहान, युवा प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोनकर, महामंत्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, किशन बघेल, सचिन सोनी, रोहित सोनी, गौरव ढाकरे, महेश ठाकुर, धर्म दिवाकर, शैलेंद्र यादव उर्फ सेलू, हिमांशु जैन, सौरभ ठाकुर, भारत वर्मा, हेमंत सिसोदिया, धर्म दिवाकर, डालचंद, मुकेश चौधरी, सौरभ ठाकुर, शैलेंद्र यादव उर्फ सेलू, हिमांशु जैन, सचिन राजपूत, भारत वर्मा, हेमंत सिसोदिया, नितिन ठाकुर, लोकेश कुशवाहा, अमित खत्री, व्यापार प्रकोष्ठ महानगर बलवंत जैन, राजीव जैन, दीपक जैन, सुरेंद्र सिंह परिहार, मोहित जैन, कुशाल गुप्ता, नितिन जैन, प्रशांत कुमार, अमित जैन, आकाश जैन, रॉबिन जैन, अजय गुप्ता, कमल किशोर उर्फ राहुल, विनोद कश्यप, अजय माहोर समेत सेकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। युवा वाहिनी प्रदेश संरक्षक रवि अरोड़ा के संरक्षण प्राप्त हुआ।

प्रेम पच्चीसा (भाग 12)

रोहन और माया की रातें अब नींद से कोसों दूर हो चुकी थीं। राशि की बीमारी ने उनके घर को जैसे उदासी की चादर से ढक दिया था। छोटी सी राशि, जो अभी सिर्फ़ पांच साल की थी, को डॉक्टरों ने बताया था कि उसको अस्थमा की बीमारी में समस्या है और इलाज़ के लिए कम से कम पचास हज़ार रुपये लगेंगे।

रोहन, फिल्म कंपनी के दलाल मेहता जी से अनुबंध साइन करके अग्रिम राशि लेकर राशि का इलाज़ भोपाल में करा रहा था और माया पत्रकार होने के साथ साथ घर से आस पास के ग़रीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, दोनों मिलकर मुश्किल से घर चला पा रहे हैं। कहते हैं कि टूटना सितारों से सीखना होगा जो टूट कर भी ज़मी पर नहीं गिरते।

रोहन को अपनी नानी की बचपन की कहानी याद आई कि दो बीजों की सोच एक बार दो बीज धरती में पड़े थे। पहला बीज सोचता था, "मैं बड़ा वृक्ष बनूंगा, लोगों को छाया दूंगा, फल दूंगा। मुझे प्रकाश और जल की ओर बढ़ना है।" दूसरा बीज डरता था, "अगर मैं अंकुरित हुआ तो कीड़े मुझे खा सकते हैं, धूप मुझे जला सकती है। मैं यहीं सुरक्षित हूँ। समय बीता। पहला बीज अंकुरित हुआ, बढ़ा और एक विशाल वृक्ष बन गया। दूसरा बीज वहीं मिट्टी में सड़ गया। जिसने सकारात्मक सोचा, वह विकसित हुआ। जिसने भय और नकारात्मकता को चुना वह समाप्त हो गया। रोहन पहला बीज बनना चाहता है।

मेहता जी मुंबई में फिल्मों में सिचुएशन गीत लिखने / लिखवाने का काम करते थे। अनुबंधित की शर्तें पूरी नहीं हो रही थीं। मेहता जी का कहना था कि एक साल तक रोहन उन्हें उनके बताए अनुसार गीत लिख कर देगा।

हर रात रोहन सोचता, कैसे भी करके वह मेहता जी का काम एक साल में शर्त अनुसार पूरा करेगा। इधर राशि का स्वस्थ सुधार रहा था। डॉक्टर ने अस्थमा की दवाएं हमेशा खाने के लिए प्रिसक्रिप्शन लिखकर माया को दिया और राशि को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया।

शाम को माया ने रोहन को फोन करके बताया कि राशि अब घर आ गई उसको लंबे समय तक अस्थमा की दवाएं और धूल से दूर रखना होगा क्योंकि डस्ट से उसे एलर्जी है। रोहन ने सुकून की सांस ली और वीडियो कॉल करके राशि से बात करते हुए, अपना गम छुपाकर एक चुटकुला भी सुनाया। दोनों की बातें सुनकर माया की आँखें डबडबा गईं।

रोहन, मेहता जी के अनुबंध अनुसार पूरे साल काम करते हुए खाली समय में अपने अतीत और सभी रिश्तों को आधार बनाकर एक कहानी संग्रह लिख चुका है। भोपाल में माया एक दिन संप्रेषण- गृह में गैर सरकारी संगठन आदर्श समाज की संयोजिका, मालती जी के साथ बाल अपचारियों को खिलौने और पुस्तकें भेंट करने बाल संप्रेषण गृह अर्थात 18 साल से कम आयु के बच्चों का सुधार घर।

सुधार गृह की स्थिति और बाल अपचारियों की गतिविधि देखकर माया विचलित हो जाती है और संयोजिका मालती जी से प्रश्न करती है कि,,

(भाग 13)

- राजेन्द्र रंजन गायकवाड़
सेवा निवृत केंद्रीय जेल अधीक्षक

गणेश उत्सव पर विशेष कविता
मंगलकार्य तुम्हारे बिन नहीं हो पाता...!

हे प्रथम पूज्य गणेश बुद्धि के प्रदाता,
मंगलकार्य तुम्हारे बिन नहीं हो पाता।
जब कभी कोई किसी संकट में होता,
तभी हमें ही नाम तुम्हारा याद आता।
पंचतत्व में जल के ₹स्वामी₹ कहलाते,
विघ्न विनाशक-सिध्दी दायक हे पाते।

हर वर्ष करते गणेशोत्सव का आह्वान,
सबके विघ्नहरो करें तुम्हारा गुणगान।
आस्था-भक्ति से करों सब पे उपकार,
रिद्धि-सिद्धि के दाता सदा दो वरदान।
निश्छल मन से करों गणेश आराधना,
भक्ति-भाव से पूर्ण हो सबकी साधना।

शौर्य, साहस व नेतृत्व के प्रतीक गणेश,
हे विशिष्ट गुणों से बखान मंगल प्रवेश।
गज मस्तक विवेकशील, कुशाग्र बुद्धि,
ऐसे प्रथम पूज्य गणराया करते शुद्धि।
सूक्ष्म दृष्टि के प्रेरक 'लम्बोदर' के कान,
सुनें वे बातें उन सबकी जो पधारे धाम।

संजय एम तराणेकर

अपने डॉक्टर स्वयं बनें

अगर हम कुछ खाने पीने की चीज़ों में सुधार करते हो तो अपने शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद हो सकती है, हम अपने डॉक्टर स्वयं बन सकते है,

1. नमक केवल सेन्धा प्रयोग करें। थायराइड, बी.पी., पेट ठीक होगा।
2. कुकर स्टील का ही काम में लें। एल्युमिनियम में मिले lead से होने वाले नुकसानों से बचेंगे।
3. तेल कोई भी रिफाइंड वाला न खाकर केवल तिल, सरसों, मूंगफली, नारियल प्रयोग करें। रिफाइंड में बहुत केमिकल होते हैं जो शरीर में कई तरह की बीमारियाँ पैदा करते हैं।
4. सोयाबीन बड़ी को 2 घण्टे भिगो कर, मसल कर ज़हरीली झाग निकल कर ही प्रयोग करें।
5. देसी गाय के घी का प्रयोग बढ़ाएं। अनेक रोग दूर होंगे, वजन नहीं बढ़ता।
6. ज्यादा से ज्यादा मीठा नीम/कढ़ी पत्ता खाने की चीजों में डालें, सभी का स्वास्थ्य ठीक करेगा।
7. ज्यादा व्यंजन लोहे की कढ़ाई में ही बनाएँ। आयरन की कमी किसी को नहीं होगी।
8. भोजन का समय निश्चित करें, पेट ठीक रहेगा। भोजन के बीच बात न करें, भोजन ज्यादा पोषण देगा।
9. नाश्ते में अंकुरित अन्न शामिल करें। पोषक विटामिन, फाइबर मिलेंगें।
10. सुबह के खाने के साथ देशी गाय के दूध का बना ताजा दही लें, पेट ठीक रहेगा।
11. चीनी कम से कम प्रयोग करें। उसकी जगह गुड़ खाँड़ का प्रयोग करें।

वेलनेस न्यूरोथेरेपी दिवस पर छत्तीसगढ़ के चंद्रप्रकाश को दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया

छत्तीसगढ़ में भी ज्यादा से ज्यादा वेलनेस न्यूरोथेरेपी सेंटर खुलें : चंद्रप्रकाश

सुनील चिंचोलकर

बिलासपुर, छत्तीसगढ़। "आरोग्य पीठ₹ के तत्वावधान में दिल्ली स्थित श्री गुरु रामराय उदासीन आश्रम, आराम बाग में 14वाँ वेलनेस न्यूरोथेरेपी दिवस एवं 12वाँ दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर देशभर से 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रहीं। उन्होंने कहा कि "जहाँ एलोपैथी और अन्य चिकित्सा पद्धतियों का मार्गदर्शन समाप्त हो जाता है, वहीं से न्यूरोथेरेपी की शुरुआत होती है।" साथ ही दिल्ली में न्यूरोथेरेपी के और अधिक केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस राष्ट्रीय आयोजन में छत्तीसगढ़ से एकमात्र प्रतिभागी के रूप में चंद्रप्रकाश कोशारिया (निवासी ग्राम चिल्फी, जिला मुंगेली, वर्तमान में बिलासपुर) ने प्रतिनिधित्व किया। आरोग्य पीठ द्वारा उन्हें अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी के दर्शन निदान प्रशिक्षण का प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण 22, 23 और 24 अगस्त 2025 तक चला।

चंद्रप्रकाश कोशारिया फिटनेस ट्रेनर, एडवांस पर्सनल ट्रेनर, कायरोप्रैक्टर, ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट, पावर मूव्स एवं एरोबिक, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन एवं डाइट, न्यूरोथेरेपिस्ट तथा एडवांस न्यूट्रिशन एवं डाइटीशियन सर्टिफाइड ट्रेनर है। वे अब तक के खेल, थेरेपी, फिटनेस, हेल्थ से संबंधित 50+ प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुके हैं।

अपनी उपलब्धि पर चंद्रप्रकाश कोशारिया ने कहा कि ₹यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं छत्तीसगढ़ से इस राष्ट्रीय मंच पर एकमात्र प्रतिनिधि बना। न्यूरोथेरेपी स्वास्थ्य क्षेत्र में नई आशा है और मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी इसके अधिक केंद्र खुलें, जिससे आमजन इसका लाभ ले सकें।"

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित ट्राइब्यूनल (NGT) के आदेश को रद्द किया: एनजीटी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली - माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में M/s C.L. Gupta Export Ltd. बनाम आदिल अंसारी मामले में राष्ट्रीय हरित ट्राइब्यूनल (NGT) के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें NGT ने मुरादाबाद की एक हैंडिक्राफ्ट निर्यातक कंपनी पर अवैध भूजल दोहन, गंगा की सहायक नदियों में अनुपचारित अपशिष्ट जल डिस्चार्ज, और जल व वायु प्रदूषण अधिनियमों के उल्लंघन के आरोप में ₹50 करोड़ का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया था। NGT ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया था।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. चंद्रन की खंडपीठ ने 25 अगस्त 2025 को अपने फैसले में निम्नलिखित आधारों पर NGT के आदेश को रद्द किया:

अधिकार क्षेत्र से परे कार्यवाही: NGT ने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया, क्योंकि NGT अधिनियम, 2010 की धारा 15 केवल पर्यावरण संरक्षण, पुनर्स्थापन और मुआवजे के लिए नागरिक उपायों तक सीमित है। NGT को आपराधिक जांच शुरू करने या ED को PMLA के तहत कार्रवाई का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि पर्यावरणीय उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग के बीच सीधा संबंध सिद्ध न हो।

मनमाना जुर्माना: ₹50 करोड़ का जुर्माना कंपनी के वार्षिक टर्नओवर (₹500 करोड़) के आधार पर लगाया गया, बिना पर्यावरणीय क्षति की मात्रा या उल्लंघन के अनुपात को स्थापित किए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुआवजा वास्तविक क्षति पर आधारित होना चाहिए, न कि दंडात्मक।

अनावश्यक और असंगठित आदेश: NGT का 145 पेज का आदेश अनावश्यक रूप से लंबा, असंगत और कानूनी विश्लेषण से रहित था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ₹कानून का उल्लंघन₹ और अनुचित बताया।

हालांकि, कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा निगरानी और ऑडिट के NGT के निर्देशों को बरकरार रखा, जिससे स्वतंत्र कार्रवाई की संभावना बनी रही। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उन पिछले निर्णयों के अनुरूप है, जैसे कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम NGT (दिसंबर 2024), जहां प्रक्रियात्मक खामियों के कारण जुर्माने को रद्द किया गया था।

राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव ने इस फैसले का स्वागत करते हुए NGT की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। डॉ. यादव ने कहा, ₹NGT अपने मूल उद्देश्य—पर्यावरण संरक्षण—से भटककर एक उगाही का माध्यम बन गया है, जो जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है। ट्रक ट्रांसपोर्ट उद्योग पर NGT के कई आदेश, जैसे डीजल प्रतिबंध और उत्सर्जन मानक, अव्यवहारिक और अन्यायपूर्ण रहे हैं, जो परिवहन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाते हैं।"

डॉ. यादव ने आगे कहा, "सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला NGT को अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम करने का स्पष्ट संदेश देता है। हम मांग करते हैं कि NGT पारदर्शी, तथ्य-आधारित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण और उद्योगों के बीच संतुलन बना रहे।" राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा सरकार और संबंधित प्राधिकरणों से अपील करता है कि वे NGT के कामकाज की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि पर्यावरणीय नीतियां उद्योगों, विशेषकर ट्रक ट्रांसपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों, के लिए निष्पक्ष और व्यवहार्य हों।

डॉ. राजकुमार यादव, "उफ्तत्सा"
राष्ट्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी)

कौन कब मंत्री था यह मायने नहीं रखता क्योंकि यह अस्पताल निर्माण घोटाले की जांच है : वीरेन्द्र सचदेवा

मुख्य संवाददाता/ सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी एक भ्रमजाल पार्टी है जिसके नेता अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के बचाव के लिए भ्रम फैलाने के माहिर खिलाड़ी हैं।

आज जब लम्बे समय से पंजीकृत अस्पताल निर्माण घोटाले के संदर्भ में जांच एजेंसी ई.डी. ने पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के निवास पर रेड किया तो हमेशा की तरह बौखलाए ₹आपऱ नेताओं ने भ्रमजाल फैलाना शुरू कर दिया।

आज "आप" नेता कह रहे हैं जब अस्पताल निर्माण का निर्णय हुआ उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे, यह बिल्कुल ठीक है है अस्पताल निर्माण का निर्णय सौरभ भारद्वाज ने नहीं लिया पर क्या ₹आपऱ नेता इस सच को नाकार सकते हैं कि जिस वक्त अस्पताल निर्माण चलता रहा है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री थे।

आम आदमी पार्टी नेता बतायें कि क्या यह सच नहीं कि वह अपने शासनकाल एक भी घोषित अस्पताल का निर्माण पूरा नहीं कर सके क्योंकि जितने भी अस्पतालों के निर्माण की घोषणा कि वह आधी अधूरी योजना से भवन राशि आवंटित कर की।

उनकी सरकार ने केवल ईट गाढ़े की बिल्डिंग का बजट दिया और अस्पताल निर्माण की घोषणा कर दी। केजरीवाल सरकार ने ना उनके बिजली पानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना ऑपरेशन थियेटर बनाने का फंड दिया ना वार्ड निर्माण या अन्य मैडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड कभी आवंटित किया।

केजरीवाल सरकार के शासन में निर्माण जारी रखने के लिए तक छोटे छोटे टेंडर या मंत्री स्तर पर स्वीकृत कर आकस्मिक सामग्री खरीद का खेल लगातार चलता रहा है।

इस सब फंड स्वीकृति खेल के दौरान सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया एवं सौरभ भारद्वाज मंत्री रहे और उनकी इसमे गम्भीर भूमिका रही।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने ₹आपऱ नेताओं से पूछा है कि क्या ई.डी. जांच को फर्जी बताने वाले सौरभ भारद्वाज शपथ लेकर यह कह सकते हैं कि उन्होंने अस्पताल निर्माण से जुड़ी आकस्मिक या अतिरिक्त टेंडर खरीद के लिए स्वास्थ्य मंत्री के नाते कोई स्वीकृति नहीं दी ?

उन्होंने कहा है कि कौन कब मंत्री था यह मायने नहीं लगता क्योंकि यह अस्पताल निर्माण घोटाले की जांच है, अस्पताल बनाने के निर्णय की नहीं।

सचदेवा ने कहा है कि यह केवल 11 स्थाई अस्पतालों के निर्माण में लूट का मामला नहीं, अभी तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से जानना चाहती है कि आखिर क्यों वह एक भी नया स्थाई अस्पताल पूरा करवाना तो दूर, कोविड़काल में घोषित 7 अस्थाई अस्पताल भी पूरे नहीं करवा सके थे ?

आईडीबीआई बैंक ने रणनीतिक सीएसआर के तहत सफदरजंग अस्पताल को प्रदान किये चिकित्सा उपकरण

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली

नई दिल्ली। आईडीबीआई बैंक ने सामाजिक उत्तरदायित्व और स्वास्थ्य सेवा उन्नयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, आज अपने व्यापक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के तहत सफदरजंग अस्पताल को औपचारिक रूप से चिकित्सा उपकरण सौंपे। इस योगदान में आपातकालीन चिकित्सा विभाग के लिए ट्रॉलियों वाली दो उन्नत ईसीजी मशीनें और पैथोलॉजी विभाग के लिए एक परिष्कृत फ्यूम एक्सट्रैक्टर शामिल हैं। उपकरण सौंपने के समारोह में अस्पताल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, आईडीबीआई बैंक के अधिकारी और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर शामिल हुए, जो अस्पताल की नैदानिक क्षमताओं और सुरक्षा मानकों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ट्रॉलियों वाली दो अत्याधुनिक ईसीजी मशीनें आपातकालीन रोगी देखभाल के लिए हृदय निगरानी क्षमताओं को बढ़ाएँगी और महत्वपूर्ण हृदय मूल्यांकन के लिए प्रतिक्रिया समय में भी सुधार करेंगी। उन्नत फ्यूम एक्सट्रैक्टर एक आवश्यक प्रयोगशाला सुरक्षा उपकरण है जिसे खतरनाक फॉर्मेल्डिहाइड वाष्प और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वीओसी) को पकड़ने और हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऐसे धुएँ के लंबे समय तक संपर्क में रहने से जलन, श्वसन संबंधी समस्याएँ और यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है, जिससे प्रयोगशाला कर्मियों के लिए सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सफदरजंग अस्पताल के निदेशक डॉ. संदीप बंसल ने इस योगदान के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा:

"आईडीबीआई बैंक का यह उदार योगदान हमारी स्वास्थ्य सेवा वितरण क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। ईसीजी मशीनें हमारे आपातकालीन चिकित्सा विभाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी, जिससे हमारी चिकित्सा टीम महत्वपूर्ण क्षणों में तेज़ और अधिक सटीक हृदय मूल्यांकन प्रदान कर सकेगी। हमारे पैथोलॉजी विभाग के लिए फ्यूम एक्सट्रैक्टर हमारे प्रयोगशाला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण तैयार करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वे इष्टतम परिस्थितियों में अपना महत्वपूर्ण कार्य जारी रख सकें। कॉर्पोरेट संस्थाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के बीच ऐसी साझेदारियाँ हमारे स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने और अंततः अधिक लोगों की जान बचाने के लिए आवश्यक हैं। हम सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति आईडीबीआई बैंक की दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। आईडीबीआई बैंक के ज़ोनल हेड श्री शशांक दीक्षित ने बैंक के सीएसआर दर्शन पर प्रकाश डाला। आईडीबीआई बैंक में हमारा मानना है कि कॉर्पोरेट सफलता को केवल वित्तीय प्रदर्शन से नहीं, बल्कि समाज की भलाई में हमारे योगदान से मापा जाना चाहिए। हमारे सीएसआर ढांचे के तहत स्वास्थ्य सेवा हमारे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है, और सफदरजंग अस्पताल में यह योगदान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का समर्थन करने की हमारी प्रतिबद्धता के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। यह पहल हमारे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले समुदायों में स्थायी प्रभाव पैदा करने के हमारे दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाती है, और हम इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा वितरण को और मज़बूत करने के लिए सफदरजंग अस्पताल के साथ अपनी साझेदारी जारी रखने के लिए तत्पर हैं।" कार्यक्रम में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वारु बांबा, वीएमएमसी की प्रिंसिपल प्रोफेसर गीतिका खन्ना, सभी अतिरिक्त एमएस, एचओडी, सीएसआर समिति के सदस्य, श्री मनीष पाठक, जीएम, क्षेत्रीय प्रमुख और सुश्री श्रुति शर्मा, शाखा प्रबंधक, ग्रीन पार्क उपस्थित थे।

ये तकनीकी पहल विकसित दिल्ली के विज़न को पूरा करेंगी: परवेश साहिब सिंह

मुख्य संवाददाता /सुषमा रानी

नई दिल्ली। माननीय लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री परवेश साहिब सिंह ने भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना संस्थान (बीआईएसएजी-एन) और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ बैठक में दिल्ली की सड़कों के बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा के लिए तकनीकी समाधानों के एकीकरण पर जोर दिया।

सड़क संपत्ति मैपिंग, परियोजना निगरानी प्रणाली, गड्ढों और जलभराव डैशबोर्ड, डार्कस्पॉट निगरानी और स्ट्रीट लाइट ट्रैकिंग प्रणाली महत्वपूर्ण नागरिक-केंद्रित पहल हैं, जिन्हें माननीय मंत्री ने जल्द से जल्द शुरू करने के आदेश दिए। यह राजधानी में कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।

"पीडब्ल्यूडी दिल्ली की सड़कों के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये डिजिटल प्लेटफार्म हमें वास्तविक समय में निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और दीर्घकालिक समाधानों में मदद करेंगे, जिससे आम लोग हर कदम पर सुरक्षा और सुविधा का अनुभव कर सकें," मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा।

बैठक में, मंत्री ने पीडब्ल्यूडी सड़क संपत्ति मैपिंग एप्लिकेशन की समीक्षा की, जो निर्माणाधीन है। यह समाधान सभी सड़क संपत्तियों का जियो-टैगिंग के साथ डिजिटल इन्वेंट्री बनाएगा।

यह पहल पारदर्शी योजना, कुशल रखरखाव और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करेगी। यह प्रणाली एक डैशबोर्ड के माध्यम से ब्लैक स्पॉट, अतिक्रमण और सड़क सुरक्षा बुनियादी ढांचे में कमियों की पहचान करने में भी मदद करेगी।

मंत्री ने आगे अधिकारियों को निर्देश दिया कि डैशबोर्ड में विधानसभा-वार रिपोर्ट प्रदान करने की सुविधा सुनिश्चित की जाए ताकि अधिक जवाबदेही और निगरानी हो सके।

बैठक के दौरान, एक परियोजना निगरानी प्रणाली की समीक्षा की गई, जो ₹1 करोड़ से अधिक की महत्वपूर्ण पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं की निगरानी करेगी। यह प्रणाली अधिकारियों को प्रगति की निगरानी करने, समस्याओं की पहचान करने और हितधारकों से वास्तविक समय के अपडेट के साथ सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम बनाएगी।

पीडब्लूडी मंत्री ने कहा कि यह प्रणाली परियोजनाओं को समय पर, कुशलता और पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरा करने में सुनिश्चित करेगी, जिससे नागरिकों को सीधे लाभ होगा।

मंत्री ने खराब स्ट्रीट लाइट्स की वास्तविक समय में निगरानी के लिए प्रस्तावित डिजिटल तंत्र की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली दिल्ली पुलिस, निर्वाचित प्रतिनिधियों और नागरिकों से प्राप्त रिपोर्टों को एकीकृत करेगी, जिससे तेजी से मरम्मत और सुरक्षित सड़कें सुनिश्चित होंगी।

"यह पहल दिल्ली के लोगों के कल्याण के लिए अंतर-विभागीय प्रयासों, सहयोग और अच्छे शासन की भावना को दर्शाती है," उन्होंने ने कहा।

सुरक्षा संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि एक डार्क स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जो बिना स्ट्रीट लाइट वाले क्षेत्रों को डिजिटल रूप से कैप्चर करेगा। यह प्लेटफ़ॉर्म दिल्ली में सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए डार्क स्पॉट क्षेत्रों में सुधार की प्रक्रिया को तेज करेगा।

गड्ढों और जलभराव की शिकायतों के लिए एक डैशबोर्ड भी बनाया जा रहा है, जहां नागरिकों, विभागों और सार्वजनिक प्रतिनिधियों की रिपोर्टों को तुरंत ट्रैक किया जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा।

"ये तकनीकी पहल दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित, कुशल और नागरिकों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह बनाकर विकसित दिल्ली के विज़न को पूरा करेंगी," परवेश साहिब सिंह ने कहा।

"आप" इन भाजपा रेडों से डरने वाली नहीं, हम हमेशा की तरह देश हित में ग़लत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे- केजरीवाल

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज के घर हुई ईडी की रेड को लेकर भाजपा और मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। ''आप'' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस पूरे मामले को फर्जी और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताया।

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह "आप" को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया। "आप" को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार की ग़लत नीतियों और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज "आप" की है। मोदी सरकार हमारी आवाज़ दबाना चाहती है। ये कभी नहीं होगा। "आप" बीजेपी की इन रेडों से डरने वाली नहीं। हम हमेशा की तरह देश हित में ग़लत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे।

''आप'' के वरिष्ठ नेता और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि 25 अगस्त से पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर चर्चा चल रही थी और जब यह "सच" सामने आया, तो भाजपा ने इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड कराई। सिसोदिया ने सवाल उठाया कि क्या भाजपा मानती है कि मोदी ने अपनी डिग्री के बारे में देश से झूठ बोला या भाजपा ने खुद देश को अंधेरे में रखा?

मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा का एकमात्र तरीका है कि जब कोई बड़ा मुद्दा उठता है, तो ईडी या सीबीआई के जरिए किसी के घर रेड कराकर खबर बदल दी जाए। सौरभ भारद्वाज पर रेड को उन्होंने पूरी तरह से फर्जी करार दिया, क्योंकि जिस समय के मामले (2018-19 में दिल्ली के 24 अस्पताल निर्माण परियोजनाओं) का हवाला दिया जा रहा है, उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे। सिसोदिया ने कहा कि गैर-मंत्री पर रेड डालना हास्यास्पद है और यह केवल मोदी की डिग्री विवाद से ध्यान भटकाने की साजिश है।

संजय सिंह ने सवाल उठाया कि सौरभ भारद्वाज के घर पर अचानक 26 अगस्त को ही ईडी की छापेमारी क्यों हुई? ऐसा इसलिए, क्योंकि इसका मकसद देश में चल रही "मोदी जी की फर्जी डिग्री" की चर्चा को दबाना है। भाजपा मुद्दा बदलने के लिए ऐसी कार्रवाइयां करती है। "आप" नेताओं की ईमानदारी और सच्चाई को पूरा देश जानता है और झूठे मुकदमों से न तो उन्हें परेशान किया जा सकता है, न झुकाया जा सकता है, न ही रोका जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि चाहे मोदी, अमित शाह या भाजपा कितनी भी कोशिश कर लें, वे कामयाब नहीं होंगे।

एवरीथिंगअबाउटवाटर एक्सपो 2025: सतत जल समाधानों के लिए एक वैश्विक सम्मेलन

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। अर्थ वाटर फाउंडेशन को उद्योग जगत को एवरीथिंगअबाउटवाटर एक्सपो और कॉन्क्लेव 2025 के आगामी 20वें संस्करण के बारे में बताते हुए खुशी हो रही है, जो 28 से 30 अगस्त 2025 तक हॉल नंबर 12ए, भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित होगा। जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन को समर्पित दक्षिण एशिया के सबसे बड़े आयोजन के रूप में पहचाने जाने वाले इस एक्सपो में दुनिया भर के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया जाएगा।

अपेक्षित भागीदारी और उद्योग प्रतिक्रिया

तीन दिवसीय इस प्रदर्शनी में 10,000 से अधिक आगंतुकों के आने और 150 से अधिक प्रदर्शनी कंपनियों के भाग लेने की उम्मीद है। अत्याधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन के अलावा, इस आयोजन में जल प्रबंधन की महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए डिज़ाइन किए गए 50 से अधिक उत्पादों का अनावरण भी होगा। प्रदर्शनी स्थल पहले ही पूरी तरह से बिक चुका है, जो उद्योग जगत के दृढ़ विश्वास और रुचि को दर्शाता है।

29 अगस्त 2025 को, ईटीपी, एसटीपी और जेडएलडी डिज़ाइन, गणना और समस्या निवारण पर एक उन्नत स्तर का व्यावहारिक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जो जल पेशेवरों और संयंत्र डिजाइनरों के लिए बहुमूल्य तकनीकी ज्ञान प्रदान करेगा।

वैश्विक पहुँच और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी

इस संस्करण में चीन, इटली, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, इज़राइल और जापान सहित कई देशों से अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की जाएगी। वैश्विक प्रदर्शकों और कंट्री पैवेलियनों की उपस्थिति, जल एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन में व्यापार और नवाचार के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में एक्सपो के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय कद को और पुष्ट करती है।

प्रायोजक और उद्योग भागीदार

इस आयोजन को जल क्षेत्र के कुछ सबसे प्रतिष्ठित नामों का समर्थन प्राप्त है। आईओटीए वाटर/निको नैनोबबल इंडिया कंपनी प्लैटिनम प्रायोजक के रूप में शामिल हुई है, विश्वराज एनवायरनमेंट लिमिटेड को डायमंड प्रायोजक के रूप में पुष्टि की गई है, जबकि जैन इरिगेशन और वेलस्पन डीआई पाइप्स लिमिटेड गोल्ड प्रायोजक के रूप में शामिल हैं। जिनीज़ कंपनी लिमिटेड और एनर्जेनियस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को सिल्वर प्रायोजक के रूप में पुष्टि की गई है, और मैकसन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बैज और लैनयार्ड प्रायोजक के रूप में इस आयोजन का समर्थन कर रही है। इज़राइल दूतावास आधिकारिक कंट्री पार्टनर के रूप में भाग ले रहा है, जिससे एक्सपो द्वारा बढ़ावा दिए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा।

सरकारी समर्थन और संस्थागत समर्थन

एवरीथिंगअबाउटवाटर एक्सपो 2025 को जल शक्ति मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नीति आयोग, राष्ट्रीय जल मिशन और टेरी सहित प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों और राष्ट्रीय मिशनों का प्रबल समर्थन प्राप्त है। उनकी सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करती है कि यह आयोजन जल सुरक्षा, स्थिरता और नवाचार पर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।

प्रमुख उद्योग निकायों का समर्थन

कई प्रतिष्ठित व्यापार और उद्योग संघों ने इस आयोजन को अपना समर्थन दिया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और पहुँच और भी बढ़ गई है। इनमें भारतीय सिंचाई संघ, क्रय पेशेवर मंच - भारत, आरसीसीआई, एसएमई चैंबर ऑफ इंडिया, एमआरएआई (भारतीय सामग्री पुनर्चक्रण संघ), अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, अखिल भारतीय उद्योग संघ, इंडो-ऑस्ट्रेलियन चैंबर ऑफ कॉमर्स और एसपीई इंडिया (सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स - इंडिया चैप्टर) शामिल हैं।

खेल के माध्यम से विकास और शांति को बढ़ावा

(राष्ट्रीय खेल दिवस)

विद्यार्थी जीवन में खेलों का विशेष महत्व है। खेल विद्यार्थी को सामाजिक जीवन से जोड़ते हैं और उसमें परस्पर सम्मान, अनुशासन और समर्पण की भावना का संचार करते हैं।

भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस (National Sports Day) मनाया जाता है, जोकि हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 'हॉकी के जादूगर' ने हॉकी में तीन ओलंपिक स्वर्ण पदकों सहित भारतीय खेलों में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिसने देश के खेल इतिहास में उनकी जगह पक्की कर दी है।

भारत के हॉकी वर्चस्व में ध्यानचंद:

राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत मेजर ध्यानचंद सिंह के हॉकी में शानदार करियर से जुड़ी हुई है। 29 अगस्त, 1905 को जन्मे ध्यानचंद की असाधारण प्रतिभा ने उन्हें 'हॉकी का जादूगर' नाम दिया। 1920 और 1930 के दशक के दौरान भारत के हॉकी वर्चस्व में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने देश को लगातार तीन ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए।

मेजर ध्यानचंद की विरासत:

भारतीय खेलों में मेजर ध्यानचंद के अपार योगदान को देखते हुए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वार्षिक कार्यक्रम न केवल उनकी विरासत को याद करता है, बल्कि नागरिकों को खेलों में भाग लेने और शारीरिक फिटनेस को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय खेल दिवस :खेल भावना का जश्न मनाने और शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। लोग विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भाग ले सकते हैं; जैसे कि खेल में भाग लेना, प्रतियोगिताओं का आयोजन करना और स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना।

शारीरिक और खेल कौशल को बढ़ावा :भारत भर में खेल और शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। यह राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्कृष्ट एथलीटों, कोचों और खेलों में योगदान देने वालों को सम्मानित करने का अवसर है। यह दिन स्वस्थ जीवन शैली, टीम वर्क, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने में खेलों के महत्व को रेखांकित करता है।

राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 का थीम :2025 के खेल दिवस का विषय ₹हर दिन खेलें₹ है। इसका मतलब है कि खेलों को अपनी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए, न कि सिर्फ एक विशेष अवसर।

अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 की थीम ₹समतल खेल मैदानः सामाजिक समावेशन के लिए खेल₹ है। यह थीम खेलों में उम्र, लिंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव को चुनौती देने, समान अवसर प्रदान करने और समावेशी खेल वातावरण बनाने पर जोर देती है। राष्ट्रीय खेल दिवस खेल लोगों को एकजुट कर सकते हैं, समझ को बढ़ावा दे सकते हैं और मजबूत समुदायों का निर्माण कर सकते हैं। टीमवर्क, सम्मान और एकता के माध्यम से, खेल सामाजिक बाधाओं को तोड़ने और शांति और समावेशिता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। उत्सव और जागरूकता का दिन :राष्ट्रीय खेल दिवस शारीरिक फिटनेस के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ खेल भावना का जश्न मनाने का एक अवसर है। यह दिन विभिन्न खेल गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कल्याण की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है जो एथलीटों की उपलब्धियों का सम्मान करते हुए खेल और शारीरिक गतिविधि की संस्कृति को बढ़ावा देता है। यह स्वस्थ और पूर्ण जीवन जीने में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाता है

अवनीश लोंगोवाल

स्वास्थ्य ,सबसे अच्छा मित्र और हर रिश्ते की असली बुनियाद है

मनुष्य के जीवन में यदि किसी साथी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सच्चा और स्थायी माना जाए तो वह है उसकी अच्छी सेहत। स्वस्थ शरीर और शांत मन वह नींव हैं जिन पर जीवन की सारी उपलब्धियाँ, सुख और रिश्तों का सौंदर्य टिका होता है। इंसान जब निरोग और ऊर्जावान होता है, उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास निकलता है, उसके संबंधों में आत्मीयता बनी रहती है और जीवन की हर चुनौती का सामना सहजता से किया जा सकता है। परन्तु जैसे ही शरीर या मन की सेहत डगमगाने लगती है, सबसे पहले असर मनुष्य के व्यवहार और उसके आसपास के लोगों पर दिखना शुरू हो जाता है। बीमारी केवल शारीरिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, वह मन, सोच और हर रिश्ते को प्रभावित करने लगती है।

आज का समय चुनौतियों से भरा हुआ है। आधुनिकता की तेज़ दौड़, भागदौड़ भरी दिनचर्या, असंतुलित भोजन, मानसिक दबाव, और बढ़ता प्रदूषण — ये सब मिलकर हमें जन-स्वास्थ्य के संकट के करीब पहुँचा रहे हैं। पहले के ज़माने में लोग प्राकृतिक जीवनशैली अपनाते थे, श्रम प्रधान कार्य करते थे, ताजे और पौष्टिक आहार लेते थे, जिससे स्वास्थ्य भी मजबूत रहता था और परिवार का वातावरण भी प्रेमपूर्ण बना रहता था। अब जीवन मशीनों और मोबाइल स्क्रीनों तक सिमटता जा रहा है, फास्ट फूड और तैयार भोज्य पदार्थों ने हमारी रसोई और शरीर दोनों को प्रभावित किया है। नतीजतन, शारीरिक दुर्बलता, मानसिक तनाव और सामाजिक दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन, निराशा, कुंठा और नकारात्मकता घर करने लगती है, साथ ही इंसान अपने रिश्तों से भी अनजाने ही दूर होता जाता है।

यह भी देखा जाता है कि बीमारी के समय व्यक्ति प्रायः खुद में सिमट जाता है, उलझन और चिंता से घिरा हुआ सा महसूस करता है, जिससे परिजनों के प्रति उसका व्यवहार भी बदलने लगता है। कई बार आर्थिक समस्याएँ, इलाज का बोझ और असहायता की भावना भी परिवार में मनमुटाव और रिश्तों में खटास ले आती है। धीरे-धीरे वे गहरे संबंध भी निरर्थक से लगने लगते हैं, जिन्हें कभी जीवन की सबसे बड़ी पूँजी समझा जाता था।

इसलिए सबसे जरूरी है कि हम स्वास्थ्य के महत्व को समझें और उसे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता मानें। दिनचर्या में नियमित व्यायाम, संतुलित एवं ताजा भोजन, पर्याप्त नींद, तनावमुक्त जीवनशैली और सकारात्मक सोच को अनिवार्य रूप से शामिल करें। यही आदतें आगे चलकर रिश्तों में भी मिठास बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती हैं क्यूंकि स्वस्थ व्यक्ति ही वास्तव में आनंदित रह सकता है और उसी की प्रसन्नता उसके आसपास के माहौल में भी संचारित होती है। याद रखें कि धन, यश, प्रतिष्ठा अथवा पदवी — सभी कुछ क्षणभंगुर हैं, परंतु वास्तविक सुख व संतुष्टि केवल स्वस्थ तन और मन में ही बसती है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक है कि स्वास्थ्य को नजरअन्दाज करना जीवन के मूलाधार को कमज़ोर करना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे संबंध मजबूत रहें, समाज में प्रेम, सहयोग और सद्भाव बना रहे तथा जीवन सच्चे अर्थों में खुशहाल हो तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी और अपने परिवार की सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूँजी, सबसे अच्छा मित्र और हर रिश्ते की असली बुनियाद है।

— डॉ. मुश्ताक अहमद शाह

"प्रथम व्याख्यानमाला दिवस"
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ: शताब्दी वर्ष की यात्रा और समाज में सार्थक योगदान

"समर्पण, अनुशासन और समावेशिता के माध्यम से विविधता में एकता : संघ की शताब्दी यात्रा"

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य केवल संगठन तक सीमित नहीं है। यह समाज में नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को मजबूत करने, प्रत्येक व्यक्ति में अनुशासन और समर्पण विकसित करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का कार्य करता है। संघ का दृष्टिकोण समावेशी है; यह किसी धर्म, जाति या समूह के विरोध में नहीं है। हिन्दू शब्द का अर्थ केवल धर्म नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, भक्ति और समाज के प्रति प्रतिबद्धता है। संघ समाज को गुटबंदी से मुक्त कर, विविधता में एकता स्थापित करने का कार्य करता है। शताब्दी यात्रा इस समर्पण और संगठन की पुष्टि है।

-डॉ. सत्यवान सौरभ

संगठन प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में तीन दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि संघ की विचारधारा, उसकी कार्यपद्धति और समाज-निर्माण यात्रा का जीवंत प्रदर्शन था। संघ का निर्माण भारत को केंद्र में रखकर हुआ और इसका उद्देश्य देश को विश्वगुरु बनाने में योगदान देना है। संघ की प्रार्थना "भारत माता की जय" केवल शब्द नहीं, बल्कि कार्य और समर्पण की प्रेरणा है। संघ का निर्माण धीमी और सतत प्रक्रिया का परिणाम है, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा।

संघ भले ही 'हिन्दू' शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन इसका मर्म केवल धर्म तक सीमित नहीं है। इसमें समावेश, मानवता और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना निहित है। संघ का उद्देश्य किसी विरोध या प्रतिस्पर्धा के लिए खड़ा होना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को संगठित करके देश की एकता बनाए रखना है। संघ का कार्य स्वयंसेवकों के माध्यम से संचालित होता है, और यह कार्य नए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देने, उनमें नेतृत्व और जिम्मेदारी विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।

राष्ट्र की अवधारणा सत्ता या सरकार से परिभाषित नहीं होती। भारतीय परंपरा में राष्ट्र का अर्थ संस्कृति, आत्मचिंतन और सामाजिक चेतना से जुड़ा है। इतिहास की ओर देखने पर यह स्पष्ट होता है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय समाज में नई चेतना और आत्म-जागरूकता को जन्म दिया। इसके बाद कांग्रेस का उदय हुआ, जिसने राजनीतिक समझ और सामाजिक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। स्वतंत्रता के बाद समाज में उपजी असमानताओं और कुरीतियों को दूर करने की चुनौती बनी रही। इसी आवश्यकता ने संघ की स्थापना और उसकी भूमिका को जन्म दिया।

डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार और अन्य महापुरुषों ने समाज के दुर्गुणों को दूर करने और संपूर्ण समाज के संगठन की आवश्यकता को पहचाना। 1925 में संघ की स्थापना इस दृष्टि से हुई कि समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य मजबूत हों और राष्ट्र निर्माण में योगदान सुनिश्चित हो। 'हिन्दू' शब्द केवल धर्म नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, समर्पण और समावेश का प्रतीक है। इसमें किसी को अलग करने या विरोध करने का भाव नहीं, बल्कि सबको जोड़ने और समाज को संगठित करने का उद्देश्य निहित है।

भारत का स्वभाव सहयोग और समन्वय का है, संघर्ष का नहीं। उसकी एकता भूगोल, संसाधनों और आत्मचिंतन परंपरा में निहित है। बाहर की ओर देखने के बजाय भीतर झाँकने पर यह स्पष्ट होता है कि सभी में एक ही

तत्व है, चाहे वह अलग-अलग रूपों में क्यों न प्रकट हो। यही कारण है कि भारत माता और पूर्वज हमारे लिए पूजनीय हैं। जो व्यक्ति भारत माता और अपने पूर्वजों का सम्मान करता है, वही सच्चा हिन्दू है। शब्द बदल सकते हैं, लेकिन भक्ति और श्रद्धा की भावना समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ती है।

समाज में धीरे-धीरे लोग संघ और हिन्दू शब्द के अर्थ को समझने लगे हैं। जीवन की गुणवत्ता बेहतर होने से लोग अपने मूल परंपराओं की ओर लौटते हैं। संघ किसी को हिन्दू होने के लिए बाध्य नहीं करता; उसका उद्देश्य समाज के समग्र संगठन और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है। संघ किसी धर्म, जाति या समूह के खिलाफ नहीं है, बल्कि समावेशी दृष्टि से सभी को जोड़कर समाज को संगठित करता है।

संघ कार्य केवल संगठन तक सीमित नहीं है। उसका लक्ष्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना है। समाज में जागरूकता और अनुशासन लाना संघ का प्रमुख उद्देश्य है। संघ की कार्यपद्धति में व्यक्तिगत समर्पण और अनुशासन का विशेष महत्व है। प्रत्येक स्वयंसेवक संघ की मूल भावना और कार्य शैली को आत्मसात करता है और समाज में इसे लागू करता है। संघ का लक्ष्य यह है कि समाज में गुटबंदी न हो, बल्कि सभी को संगठित किया जाए और देश में एकता कायम रहे।

भारत की विविधता में एकता उसकी असली पहचान है। विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति और परंपराओं के बावजूद भारत की पहचान उसकी आत्मा, संस्कृति और पूर्वजों के प्रति सम्मान में निहित है। संघ का उद्देश्य इस एकता को बनाए रखना और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसमें सहभागी बनाना है। संघ का कार्य व्यक्ति निर्माण, समाज उत्थान और राष्ट्र निर्माण तीनों स्तरों पर कार्य करता है।

संघ के माध्यम से समाज में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत किया जा रहा है। संघ कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज में अनुशासन, समर्पण और सेवा भाव का संचार करता है। संघ का उद्देश्य केवल स्वयंसेवकों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक इसका प्रभाव पहुँचना है। संघ की कार्यशैली में व्यक्तिगत प्रयास और संगठनात्मक दृष्टि का संतुलन बना रहता है। संघ का लक्ष्य यह है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे और राष्ट्र निर्माण में योगदान करे।

व्याख्यानमाला ने संघ की स्थापना, हिन्दू शब्द के अर्थ, संगठनात्मक दृष्टि, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पर स्पष्ट प्रकाश डाला। संघ का उद्देश्य किसी के विरोध में नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के उत्थान में योगदान देना है। संघ की कार्यशैली, व्यक्तिगत समर्पण और संगठनात्मक दृष्टि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

इस प्रकार, संघ शताब्दी वर्ष की यह व्याख्यानमाला समाज में संघ की भूमिका, उसकी कार्यप्रणाली और उद्देश्य को समझने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। यह स्पष्ट करती है कि संघ का उद्देश्य केवल संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के समग्र उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है। संघ का कार्य व्यक्तिगत समर्पण, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से समाज को संगठित करना है।

भक्ति धाम वैलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा दिव्यांग सेवा शिविर धूमधाम से सम्पन्न

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। रुक्मणि विहार, सैक्टर-1 स्थित भक्ति धाम में भक्ति धाम वैलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, पटियाला/वृन्दावन के आठवें स्थापना दिवस के अंतर्गत कल्याणम् करोति, मथुरा के सहयोग से दिव्यांग सेवा शिविर आयोजित किया गया ।जिसमें 50 से भी अधिक दिव्यांगों को व्हीलचेयर, वॉकर, ट्राई साइकिल, पैर, कैलीपर, बैसाखी आदि का निःशुल्क वितरण किया गया।

दिव्यांग सेवा शिविर की अध्यक्षता करते हुए विश्वविख्यात भागवताचार्य कृष्ण गोपाल सुवेदी महाराज ने कहा कि चौरासी लाख योनियों में मनुष्य रूप में जन्म मिलना ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है ।इसीलिए हम सभी का यह प्रयत्न होना चाहिए, कि शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की सेवा करके उन्हें सशक्त बनाएं।

मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रमुख समाजसेवी व वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने कहा कि भक्ति धाम वैलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट अत्यन्त सेवाभावी व परोपकारी संस्था है ।इसके द्वारा जो सेवा कार्य किए जा रहे हैं,वे अति प्रशंसनीय हैं।

भक्ति धाम वैलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष के. एल. बंसल एवं मुख्य सलाहकार डॉ. आर. के. गर्ग ने कहा कि दीन दुखियों, विकलांगों, निर्धनों, निराश्रितों, असहायों आदि की निस्वार्थ सेवा करना ही हमारे ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है ।इसीलिए हमारे ट्रस्ट के द्वार श्रीधाम वृन्दावन के अलावा देश के अन्य स्थानों पर भी समय-समय पर अनेक सेवा कार्य किए जा रहे हैं।

भक्ति धाम वैलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट (रजि.) के सचिव संदीप कुमार सिंघला व कोषाध्यक्ष रामशरण गुप्ता ने कहा कि भक्ति धाम वैलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आज दिव्यांग बालकों को उनसे सम्बन्धित जो उपकरण व अन्य सामग्री निःशुल्क वितरित की गई है,वह समाजसेवा के क्षेत्र में अत्यंत सराहनीय कार्य है ।इसके लिए हम इस ट्रस्ट एवं उसके सभी पदाधिकारियों के अत्यंत आभारी हैं।

इस अवसर पर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेश गोयल, कर्म चंद्र गोयल, अशोक बंसल, मुकेश बंसल, सुधीर सिंगला, जय कुमार गुप्ता, राजकुमार गोयल, मेघराज बंसल, प्रेम कुमार, डॉ. राधाकांत शर्मा, नेहा गोयल, रूपाली सिंगला, संगीता लवानियां, कल्याणम् करोति, मथुरा की टीम से प्रह्लाद पाण्डेय, लोकेश बिष्ट, राजेंद्र नेगी, कुलदीप शर्मा, महिपाल, मोहन गर्ग, अशोक आदि के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे ।शिविर का समापन वृहद भंडारे के साथ हुआ ।जिसमें असंख्य व्यक्तियों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया।

डॉक्टरों की लापरवाही से कानपुर के डफरिन अस्पताल में दो नवजात की मौत : हंगामा

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही लोगों को असमय ही मौत का शिकार बनाने में लगातार सफल है ,जिसके क्रम में यहां के महिला चिकित्सालय डफरिन में भी दो नवजात शिशुओं की मौत हो गई, जिसके खिलाफ दोनों गर्भवती महिलाओं के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया ।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों और फिर डॉक्टरों से पूछताछ की। इसके बाद दोनों के परिजनों को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया।

इसमें पहली घटना का संबंध शुक्लागंज निवासी ऑटो चालक मनोज वर्मा से है। मनोज आज मंगलवार सुबह अपनी पत्नी निधि कश्यप को लेकर डफरिन हॉस्पिटल पहुंचे थे। इस दौरान दर्द से तड़पती उसकी पत्नी को देखना कोई नहीं आया। इसके बाद ज्यादा दर्द होने पर डॉक्टर ऑपरेशन थ्रिएटर में ले गए। वहां पर निधि ने एक बेटे को जन्म दिया। इसके बाद डॉक्टरों ने बेटे की हालत नाजुक बताते हुए उसे आई सी यू में ले जाने की सलाह दी।

मौके पर पहुंची पुलिस को पति मनोज ने

बताया कि जब बच्चे को आई सी यू में ले गए तो वहां पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।

इसी तरह की दूसरी घटना लालबंगला के रहने वाली अंजली चौहान के साथ हुई। अंजलि 9 माह की गर्भवती थी। परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन डॉक्टरों ने भर्ती करने से मना कर दिया था। जिसके बाद उसके बच्चे की भी मौत हो गई। घटना के विरोध में दोनों परिवारों के लोगों ने जमकर हंगामा किया। उन्हें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाकर शांत कराया। पुलिस के मुताबिक घटना की जांच की जा रही है।

दुनियाँ में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति का प्रचलन तेजी से बढ़ा- वैश्विक सहयोग की जगह प्रतिस्पर्धा व एकजुट की जगह गुटबाज़ी का माहौल बढ़ा

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक परिदृश्य आज इस बात का सटीक साक्षी है कि राजनीति और कूटनीति अब सिर्फ़ विचारधाराओं या नैतिक मूल्यों पर नहीं टिकी, बल्कि उसका केंद्र आर्थिक स्वार्थ बन चुका है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी रणनीति, नीतियों और कूटनीतिक चालों को इस आधार पर गढ़ रहा है कि उसकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मज़बूत हो, उसके संसाधनों पर उसका नियंत्रण बना रहे और वैश्विक शक्ति-संतुलन में उसकी पकड़ ढीली न हो। यह स्थिति वैश्वीकरण के उस सपने से बिल्कुल अलग है, जिसमें सबके हितों की साझेदारी की बात की जाती थी। इसके बजाय आज हम ऐसी दुनिया देख रहे हैं जहाँ हर शक्ति अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि मानते हुए, कभी सहयोग तो कभी टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ रही है ।2022 से चला आ रहा रूस-यूक्रेन संघर्ष 2026 तक वैश्विक स्वार्थ राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका और नाटो इसे लोकतंत्र बनाम तानाशाही की लड़ाई कहते हैं, लेकिन असल में यह ऊर्जा संसाधनों, हथियारों के बाजार और भू-राजनीतिक प्रभुत्व का खेल है। रूस, चीन और भारत नए ब्लॉकों (ब्रिक्स+) के जरिए अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं ।भारतीय पीएम ने दिनांक 25 अगस्त 2025 को अहमदाबाद में अपने संबोधन के दौरान कहा कि "आज दुनियाँ में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति हो रही है" ।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूँ कि यह एक साधारण सा वाक्य प्रतीत होता है, लेकिन इसमें वैश्विक राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति की गहरी परतें छिपी हुई हैं। आधुनिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों और विश्व राजनीति की दिशा को समझने के लिए इस कथन का विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, दुनियाँ में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति का प्रचलन तेजी से बढ़ा-वैश्विक सहयोग की जगह प्रतिस्पर्धा व एकजुट की जगह गुटबाज़ी का माहौल बढ़ा।

साथियों बात अगर हम वैश्विक स्तर पर आज़ आर्थिक स्वार्थकी राजनीति का नयायुग शुरू होने की करें तो आज की दुनिया राजनीतिक विचारधाराओं की बजाय आर्थिक हितों से ज्यादा संचालित हो रही है। जहाँ कभी पूँजीवाद और समाजवाद जैसी विचारधाराएँ निर्णायक हुआ करती थीं, वहीं अब राष्ट्र अपनी नीतियों को इस आधार पर गढ़ते हैं कि उनका आर्थिक लाभ और हानि किस सीमा तक होगा। देशों की विदेश नीतियाँ, सैन्य रणनीतियाँ, यहाँ तक कि सांस्कृतिक कूटनीति भी अब उसी चश्मे से देखी जाती हैं जिसमें सबसे पहले सवाल पूछा जाता है- "इससे हमारे देश को क्या फायदा है?"।

साथियों बातें कम इस संबंध में अनेक देशोंकी अपडेट स्वार्थ -संचालित नीतियों को जाननेकी करें तो (1) अमेरिका की स्वार्थ-संचालितनीतियाँः- अमेरिका की राजनीति आज सबसे स्पष्ट रूप से आर्थिक स्वार्थ पर आधारित दिखती है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर से ही ₹अमेरिका फर्स्ट₹ नीति ने यह साफ़ कर दिया था कि वैश्विक सहयोग तभी तक टिकेगा, जब तक उससेअमेरिका को लाभ है। ट्रंप ने चीन पर भारी टैरिफ लगाए, डब्लूटीओ के नियमों को चुनौती दी और नाटो सहयोगियों से रक्षा खर्च में बढ़ोतरी की मांग की ।बाइडेन प्रशासन ने भले लोकतंत्र और मानवाधिकार की भाषा अपनाई हो, लेकिन उनकी नीतियों का मूल भी अमेरिका की आर्थिक मज़बूती ही है। यूक्रेन युद्ध में खुले समर्थन का कारण भी रूस को कमजोर कर यूरोप के ऊर्जा बाजार और हथियारों के व्यापार पर अमेरिकी पकड़ बनाना है। अमेरिकी टेक कंपनियों पर चीन से दूरी बनाने का दबाव, भारत जैसे देशों में निवेश और सप्लाई- चेन शिफ्ट करना-ये सब दर्शाते हैं कि आर्थिक स्वार्थ ही विदेशनीति की दिशा तय करता है। (2) चीन का विस्तारवाद और आर्थिक हितः-चीन का मॉडल पूरी तरह आर्थिक हितों पर आधारित है। ₹बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव₹ के ज़रिये चीन ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भारी निवेश किया, ताकि उसकी कंपनियों को नए बाजार मिलें और कर्ज़ देकर राजनीतिक प्रभाव भी कायम किया जा सके। लेकिन श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ्रीकी देशों में ₹डेब्ट ट्रैप₹ की स्थिति बताती है कि चीन की नीतियाँ सहयोग से ज्यादा स्वार्थ पर आधारित हैं। दक्षिण चीन सागर में उसका आक्रामक रवैया भी समुद्री व्यापार और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण के आर्थिक उद्देश्य से जुड़ा है। अमेरिका और यूरोप से तकनीकी प्रतिस्पर्धा, सेमीकंडक्टर पर पकड़ बनाने की कोशिश, और अफ्रीका में दुर्लभ धातुओं पर अधिकार हासिल करना-ये सब दर्शाते हैं कि चीन अपनी नीतियों को सिर्फ़ आर्थिक हित के तराज़ूपर तोल रहाहै ।(3) यूरोप की दुविधाः-आदर्श बनाम आर्थिक ज़रूरतयूरोपीय संघ अक्सर जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और वैश्विक न्याय की बातें करता है। लेकिन जब बात ऊर्जा, व्यापार और बाज़ार की आती है, तो वही यूरोप आर्थिक स्वार्थ के आगे झुक जाता है। जर्मनी और फ्रांस ने वर्षों तक रूस से सस्ती गैस पर अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी की, जबकि रूस की नीतियों को लेकर आलोचना भी करते रहे। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर प्रतिबंध लगाने का दबाव अमेरिका से आया, लेकिन अब यूरोप महंगे ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। इसके अलावा, यूरोप का अफ्रीकी देशों के साथ व्यापारिक संबंध, शरणार्थी संकट को रोकने के लिए समझौते, और चीन के साथ तकनीकी सहयोग भी आर्थिक हितों की राजनीति को उजागर करता है। (4) रूस का संसाधन-आधारित स्वार्थः-रूस की राजनीति का मूल उसकी ऊर्जा और हथियारों पर आधारित अर्थव्यवस्था है। पुतिन ने बार-बार तेल और गैस को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। यूक्रेन पर आक्रमण के पीछे सिर्फ़ भू-राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक कारण भी हैं-काला सागर और डोनबास क्षेत्र पर नियंत्रण रूस के लिए औद्योगिक और ऊर्जा हितों से जुड़ा है। अफ्रीका में रूस की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और खाद्य अनाज की आपूर्ति पर उसका नियंत्रण भी आर्थिक स्वार्थ को सामने लाता है। रूस आज अपने हथियार, ऊर्जा और खनिजों को इस्तेमाल कर वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने की रणनीति अपना रहा है ।(5)भारत का संतुलनकारी रवैयाः-भारत भी इस वैश्विक परिदृश्य में अपने आर्थिक हितों को केंद्र में रख रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने रूस से सस्ते तेल की खरीद जारी रखी, भले ही पश्चिमी देशों ने दबाव बनाया। यही भारत की ₹रणनीतिक स्वायत्तता₹ की झलक है। अमेरिका और यूरोप से तकनीकी निवेश और व्यापारिक साझेदारी बढ़ाते हुए भी भारत रूस और ईरान से अपने संबंध बनाए रख रहा है ।₹मेक इन इंडिया₹ ₹आत्मनिर्भर भारत₹ और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कार्यक्रम सीधे तौर पर आर्थिक स्वार्थ से प्रेरित हैं। साथ ही, भारत जलवायु परिवर्तन की वैश्विक राजनीति में भी यह स्पष्ट करता है कि वह केवल तभी बड़े कदम उठाएगा जब विकसित देश उसके आर्थिक हितों को सुरक्षित करेंगे। (6) मध्य-पूर्वः तेल, धर्म और शक्ति की राजनीतिः-मध्य-पूर्व की राजनीति पूरी तरह तेल और गैस पर आधारित है। सऊदी अरब और यूएई ने अपनी आर्थिक नीतियों को ₹विजन 2030₹ जैसे कार्यक्रमों से विविधीकरण की ओर मोड़ा है, लेकिन उनकी प्राथमिकता अभी भी तेल निर्यात पर टिकीहै, इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष और ईरान-सऊदी प्रतिद्वंद्विता भी ऊर्जा मार्गों और क्षेत्रीय प्रभाव से जुड़ी है ।अमेरिका और यूरोप का इस क्षेत्र में दखल केवल इसलिए है कि वे तेल की निर्बाध आपूर्ति चाहते हैं। हाल ही में ब्रिक्स में सऊदी अरब और ईरान की सदस्यता भी बताती है कि आर्थिक स्वार्थ कैसे नए भू-राजनीतिक समीकरण गढ़ रहा है ।(7) अफ्रीकाः संसाधनों पर वैश्विक खींचतानः- अफ्रीका दुनिया का सबसे समृद्ध महाद्वीप है प्राकृतिक संसाधनों के मामले में। लेकिन यहाँ की राजनीति में वैश्विक शक्तियों का हस्तक्षेप साफ़ दिखता है। चीन, रूस, अमेरिका और यूरोप सब यहाँ की खनिज संपदा, ऊर्जा और बाज़ारों पर पकड़ बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कोबाल्ट, लिथियम और दुर्लभ धातुओं की वैश्विक मांग ने अफ्रीका को तकनीकी युद्ध का नया केंद्र बना दिया है। लेकिन स्थानीय जनता गरीबी और असमानता से जूझ रही है, क्योंकि वैश्विक राजनीति केवल संसाधनों को हथियाने तक सीमित है।

साथियों बात अगर हम इस परिपेक्ष में वैश्विक संस्थाएँ और आर्थिक स्वार्थ की करें तो, डब्लूटीओ, आईएमफ, विश्व बैंक जैसी संस्थाएँ सिद्धांत रूप से वैश्विक संतुलन के लिए बनी थीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन पर पश्चिमी देशों का दबदबा है और उनकी नीतियाँ अक्सर उन्हीं के आर्थिक हितों को साधती हैं। आईएमफ की शर्तों ने कई गरीब देशों को कर्ज़ जाल में फँसाया, डब्लूटीओ के नियम बड़े देशों के हितों के मुताबिक ढाले गए, और विश्व बैंक की परियोजनाएँ अक्सर पर्यावरण और स्थानीय समुदायों की कीमत पर पूरी हुईं। इसी के जवाब में ब्रिक्स, जी-20 और एससीओ जैसी संस्थाएँ उभर रही हैं, जो पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देकर अपने-अपने स्वार्थ पूरे करना चाहती हैं।

साथियों बात अगर हम तकनीकी युद्ध और डेटा की राजनीति की करें तो, आज की दुनिया में तकनीक नया हथियार है। अमेरिका और चीन 5जी, एआई, सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप डेटा प्राइवेसी के नाम पर अपने हित साध रहा है ।भारत, अफ्रीका और एशिया- प्रशांत देश इस तकनीकी प्रतिस्पर्धा में निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ₹चिप वॉर₹ ने साफ कर दिया है कि तकनीकी विकास भी अब राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक शक्ति का प्रश्न बन चुका है।

साथियों बात अगर हम जलवायु परिवर्तन की राजनीति की करें तो, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सम्मेलन और समझौते अक्सर आदर्शवादी दिखते हैं, लेकिन असलियत आर्थिक स्वार्थ से जुड़ी है। विकसित देश चाहते हैं कि विकासशील देश कार्बन उत्सर्जन कम करें, जबकि खुद उन्होंने दशकों तक प्रदूषण फैलाकर आर्थिक तरक्की हासिल की। हरित ऊर्जा, कार्बन क्रेडिट और क्लाइमेट फंड सब ऐसे उपकरण हैं, जिनका इस्तेमाल शक्तिशाली देश अपने आर्थिक हित साधने के लिए करते हैं। भारत और चीन जैसे देश यह साफ़ कह रहे हैं कि विकास की गति धीमी करना उनके हित में नहीं, जब तक विकसित देश उन्हें तकनीकी और आर्थिक मदद नहीं देंगे।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि आर्थिक स्वार्थ ही राजनीति का ध्रुवताराः-दुनियाँ की राजनीति का असली चेहरा अब आर्थिक स्वार्थ है ।चाहे अमेरिका की ₹अमेरिका फर्स्ट₹ नीति हो, चीन का बेल्ट एंड रोड, रूस की ऊर्जा कूटनीति, यूरोप की दुविधाएँ, भारत की संतुलनकारी रणनीति, या अफ्रीका-मध्यपूर्व पर वैश्विक खींचतान-सब जगह राष्ट्रीय नीतियों का ध्रुवतारा आर्थिक हित ही है। वैश्विक संस्थाएँ और समझौते भी इन्हीं हितों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। भविष्य में भी विश्व व्यवस्था इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ेगी-जहाँ सहयोग, संघर्ष और गठबंधन सब कुछ आर्थिक लाभ के आधार पर तय होंगे।

बीवाईडी का कमाल: 472.41km/h की टॉप-स्पीड से दौड़ी इलेक्ट्रिक कार; बनाया रिकॉर्ड

बीवाईडी की YANGWANG U9 Track Edition सुपरकार ने जर्मनी के ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक पर 472 .41 किमी/घंटा की टॉप स्पीड से नया इलेक्ट्रिक कार रिकॉर्ड बनाया। यह कार e4 प्लेटफॉर्म और DiSus-X आर्किटेक्चर पर बनी है जिसमें क्वाड-मोटर सिस्टम है। ड्राइवर मार्क बासेंग ने यह रिकॉर्ड बनाया जिन्होंने कहा कि नई तकनीकों के साथ इसे संभव बनाया गया। YANGWANG अब दुनिया की सबसे फ़ास्ट इलेक्ट्रिक कार बन गयी है।

नई दिल्ली। हाल ही में BYD की YANGWANG ने जर्मनी के AYP ऑटोमोटिव टेस्टिंग पापेनबर्ग टेस्ट ट्रैक पर 472.41 किमी/घंटा की स्पीड का नया ग्लोबल इलेक्ट्रिक कार के टॉप-स्पीड का रिकॉर्ड बनाया है। इस टॉप स्पीड को YANGWANG U9 Track Edition सुपरकार ने हासिल की है, जो दुनिया की सबसे फास्ट ईलेक्ट्रिक कार बन गई है।

परफॉर्मेंस रहा काफी शानदार

YANGWANG U9 Track Edition को उसी e4 प्लेटफॉर्म और DiSus-X कोर आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, जिस पर चीन में बिक रही YANGWANG U9 बेस्ड है। इसके अलावा, समें दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर उत्पादित 1200V अल्ट्रा-हाई-वोल्टेज वाहन प्लेटफॉर्म है, जिसे एक्सट्रीम स्थितियों के लिए अनुकूलित थर्मल-मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा गया है।

YANGWANG U9 ट्रैक एडिशन में e4 प्लेटफॉर्म दिया गया है, जो 30,000rpm हाई-परफॉर्मेंस मोटर्स वाला दुनिया का पहला क्वाड-मोटर सिस्टम है। यह सिस्टम प्रति मोटर 555kW की पावर जनरेट करता है, जिससे संयुक्त सिस्टम आउटपुट 3,000PS से ज्यादा हो जाता है। यह कार को 1,217PS प्रति टन का पावर-टू-वेट रेशियो देता है, जो ग्लोबल ऑटोमोटिव उद्योग में शीर्ष पर रखता है।

इसके अलावा, e4 प्लेटफॉर्म का क्वाड-मोटर इंडिपेंडेंट टॉर्क-वेक्टरिंग सिस्टम लगातार सड़क से मिलने वाली जानकारी पर नजर रखता है और प्रति सेकंड 100 से अधिक बार की अल्ट्रा-हाई फ्रीक्वेंसी पर प्रत्येक पहिये के टॉर्क को एडजस्ट करता है। इसकी वजह से यह हाई स्पीड पर भी बॉडी पोस्चर पर पूरा कंट्रोल बनाए रखता है, जिससे हिया फिसलने या ट्रैक्शन खोने का कोई मौका नहीं रहता है।

YANGWANG U9 Track Edition के फीचर्स

इसे e4 प्लेटफॉर्म + DiSus-X तकनीकी आर्किटेक्चर पर डेवलप किया गया है, जो रेसट्रैक पर बॉडी पोस्चर कंट्रोल में रखने का काम करता है। इससे ड्राइवर को अच्छी सेफ्टी मिलने के साथ ही कार को कंट्रोल में रखने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा, यांगवांग U9 ट्रैक एडिशन वर्तमान यांगवांग U9 के एयरोडायनामिक डिज़ाइन को बरकरार रखता है और इसमें एक उन्नत, वैकल्पिक कार्बन-फाइबर फ्रंट स्प्लिटर लगा है, जो पहले से ही बड़े पैमाने पर उत्पादन में है। व्हील-रिम इंटरफ़ेस पर एक अभिनव नलिंग ट्रीटमेंट, हाई-विस्कोसिटी लुब्रिकेंट के साथ मिलकर, हार्ड एक्सीलरेशन या ब्रेकिंग के दौरान टायर और रिम के बीच सापेक्ष स्लिप को कम करता है।

ड्राइवर मार्क बासेंग ने बनाया ये रिकॉर्ड

इस रिकॉर्ड को जर्मन पेशेवर ड्राइवर मार्क बासेंग के जरिए बनाया गया है, जो 2024 में पिछले ग्लोबल EV स्पीड रिकॉर्ड के पीछे थे। यांगवांग के लिए हाई-स्पीड परीक्षण पूरा करने के बाद, उन्होंने कहा कि पिछले साल, मैंने सोचा था कि मैं अपने शिखर पर पहुँच गया हूँ। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी जल्दी अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, लेकिन हम यहाँ हैं, उसी ट्रैक पर, नई तकनीकों के साथ जिन्होंने इसे संभव बनाया है।

नई स्कोडा ऑक्टेविया इलेक्ट्रिक का आया नया टीजर; सितंबर 2025 में होगी पेश, जानें क्या होगा खास

परिवहन विशेष न्यूज

स्कोडा सितंबर 2025 में म्यूनिख IAA शो में विजन ओ वैगन कॉन्सेप्ट पेश करेगी जो नेक्स्ट-जनरेशन इलेक्ट्रिक ऑक्टाविया की झलक है। टीजर से इंटीरियर और एक्सटीरियर की हल्की झलक मिलती है जिसमें कनेक्टेड विंडस्क्रीन पैनोरमिक रूफ और मिनिमलिस्ट थीम शामिल हैं। टिकाऊ पार्ट्स के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है जिसमें 3D-प्रिंटेड हेडरेस्ट भी शामिल हैं। इलेक्ट्रिक स्कोडा ऑक्टाविया को डेवलप करने के लिए SSP प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा।

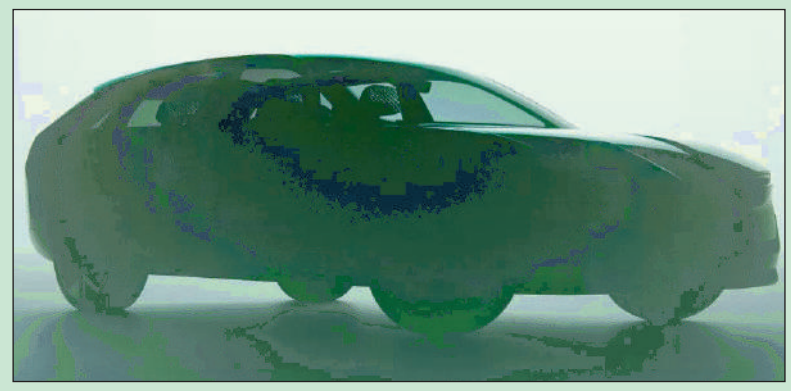

नई दिल्ली। सितंबर 2025 में म्यूनिख IAA शो होने वाला है। इस शो में Skoda अपने कई नए प्रोडक्ट और कॉन्सेप्ट मॉडल को दिखाने वाली है। इनमें Vision O wagon कॉन्सेप्ट भी होगी, जो जो नेक्स्ट-जनरेशन इलेक्ट्रिक ऑक्टाविया की झलक देगा। हाल ही में इसका एक टीजर जारी किया गया है, जिसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर की हल्की झलक दिखाई गई है।

क्या मिलेगा नया?

नई जनरेशन Skoda Octavia इलेक्ट्रिक में कनेक्टेड विंडस्क्रीन और पैनोरमिक रूफ देखने के लिए मिला है। इसमें मिनिमलिस्ट थीम भी देखने के लिए मिली है। यह भी लगता है कि कॉन्सेप्ट के बीच में एक बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है। इसके टीजर में टिकाउ पार्ट्स के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। इसमें 3D-प्रिंटेड हेडरेस्ट देखने के लिए मिला है। स्कोडा का कहना है कि ये हेडरेस्ट खाद बनाने योग्य, पौधों पर आधारित सामग्रियों से बने हैं। यह ब्रांड के पर्यावरणीय संरक्षण और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रयासों के अनुरूप है।

इससे पहले की गई जारी टीजर में इस कॉन्सेप्ट के बाहरी झलक देखने के लिए मिली थी। इससे पता चलता है कि नेक्स्ट-जनरेशन इलेक्ट्रिक ऑक्टाविया का डिजाइन और स्टाइलिंग पूरी तरह से अलग होगा। इसमें एक पीछे की ओर झुकी हुई विंडशील्ड, हल्की ढलान वाली रूफलाइन, एक ज़्यादा झुकी हुई रियर विंडशील्ड और स्पोर्टी टेल लाइट्स शामिल हैं।

इसके अलावा, इसमें शार्प एलईडी DRL, टर्न सिग्नल वाले ORVM और एक रूफ-माउंटेड स्पॉइलर भी दिया जा सकता है। इसका ओवरऑल प्रोफाइल बेहतर एयरोडायनामिक्स के हिसाब से बनाया गया है, जो इसकी अपील को बढ़ाता है और संभावित रूप से वाहन की रेंज को भी बेहतर बना सकता है। स्कोडा के अनुसार, यह कॉन्सेप्ट कार निर्माता की नई 'मॉडर्न सॉलिड' डिज़ाइन भाषा की झलक देता है, जिसका उपयोग इसकी अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक कारों में किया जाएगा।

इस प्लेटफॉर्म पर होगी डेवलप

इलेक्ट्रिक Skoda Octavia को डेवलप करने के लिए SSP प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका पहले इस्तेमाल Volkswagen ID.Golf में भी किया जाएगा। दोनों को 2029 तक बिक्री के लिए उपलब्ध कराने की योजना है। SSP प्लेटफॉर्म, VW के PPE प्लेटफॉर्म की तुलना में छोटा है। हालांकि, नई ऑक्टाविया का व्हीलबेस VW ID.Golf से लंबा होगा। इससे इसके इंटीरियर में ज़्यादा जगह और संभावित रूप से बड़ा बूट स्पेस मिल सकता है। SSP प्लेटफॉर्म 800-वोल्ट चार्जिंग आर्किटेक्चर का उपयोग करता है, जिससे तेज चार्जिंग मिलती है।

किआ सेल्टोस की नई जेनरेशन जल्द होगी लॉन्च, भारत में पहली बार दिखी, क्या होंगे बदलाव

किआ सेल्टोस वाहन निर्माता किआ की ओर से भारत में कई सेगमेंट मे एमपीवी और एसयूवी को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी की नई जेनरेशन को जल द लॉन् च करने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। एसयूवी की नई जेनरेशन को लेकर क या जानकारी सामने आई है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में कई वाहन निर्माताओं की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। किआ की ओर से भी एसयूवी सेगमेंट में सेल्टॉस को ऑफर किया जाता है। इस एसयूवी की नई जेनरेशन को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी की नई जेनरेशन की क्या जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Kia Seltos की नई जेनरेशन होगी लॉन्च

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किआ की ओर से सेल्टॉस की नई जेनरेशन को भारतीय बाजार में जल्द लॉन्च किया जा सकता है। निर्माता की ओर से इसे लॉन्च करने से पहले टेस्ट किया जा रहा है।

मिली क्या जानकारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी के लॉन्च से पहले इसे टेस्ट किया जा रहा है। जिस दौरान इसे पहली बार भारत के हैदराबाद में देखा गया है। जबकि इसके पहले कई देशों में भी इसे देखा गया है। नई जेनरेशन सेल्टॉस को नई एलईडी हेडलाइट्स, ब्लैक रूफ रेल, ब्लैक अलॉय व्हील्स, ड्यूल टोन ओआरवीएम, ट्रिपल स्क्रीन, ईवी9 की तरह सीट्स, ड्यूल जोन ऑटो एसी, पावर्ड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलैस फोन चार्जर, छह एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, Level-2 ADAS, टीपीएमएस और कई फीचर्स को दिया जा सकता है।

मिलेंगे इंजन के विकल्प

रिपोर्ट्स के मुताबिक किआ की ओर से सेल्टॉस की नई जेनरेशन को कई इंजन विकल्पों के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इसमें पेट्रोल और डीजल के साथ ही हाइब्रिड तकनीक को भी दिया जा सकता है। जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प दिए जा सकते हैं।

कब होगी लॉन्च

अभी किआ की ओर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि एसयूवी को भारतीय बाजार में 2026 तक लॉन्च किया जा सकता है।

किनसे मिलेगी चुनौती

किआ की सेल्टॉस को मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसे Honda Elevate, Maruti Grand Vitara, MG Hector, Mahindra Scorpio जैसी एसयूवी से चुनौती मिलती है।

ओला इलेक्ट्रिक के सभी सात जेन 3 स्कूटरों को मिला पीएलआई सर्टिफिकेशन, कंपनी को बिक्री पर मिलेगा 13-18% का प्रोत्साहन

ओला इलेक्ट्रिक को जेन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो के लिए PLI स्कीम के तहत कंप्लायंस सर्टिफिकेशन मिला है। ARAI ने यह सर्टिफिकेशन ओला के सात S1 जेन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटरों के सभी मॉडलों के लिए दिया है। इस सर्टिफिकेशन के बाद कंपनी को बिक्री मूल्य के अनुसार प्रोत्साहन राशि मिलेगी जिससे लागत और मार्जिन को मज़बूती मिलेगी। ओला इलेक्ट्रिक के Gen 2 और Gen 3 दोनों स्कूटर अब PLI-प्रमाणित हैं।

नई दिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक को जेन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो के लिए ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI) स्कीम के तहत कंप्लायंस सर्टिफिकेशन मिला है। भारी उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाली ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) ने यह सर्टिफिकेशन दिया है, जो ओला के सात S1 Gen 3 इलेक्ट्रिक स्कूटरों के सभी मॉडलों के लिए मान्य है। इस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता कंपनी को निर्धारित बिक्री मूल्य के 13 से 18 प्रतिशत तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके साथ, ओला इलेक्ट्रिक के Gen 2 और Gen 3 दोनों स्कूटर पोर्टफोलियो अब PLI-प्रमाणित हो गए हैं।

Gen 3 स्कूटर के मॉडल

Ola Electric के Gen 3 पोर्टफोलियो में 7 इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल है। इस पोर्टफोलियों के तहत ग्राहकों को S1 Pro 3 kWh, S1 Pro 4 kWh, S1 Pro+ 4 kWh, S1 X 2 kWh, S1 X 3 kWh, S1 X 4 kWh, और S1 X+ 4 kWh इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऑफर किया जाता है।

लागत और मुनाफे पर प्रभाव

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे Gen 3 स्कूटरों के लिए PLI सर्टिफिकेशन हासिल करना, जो हमारी अधिकांश बिक्री का हिस्सा हैं, मुनाफे की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सीधे तौर पर हमारी लागत संरचना और मार्जिन को मज़बूत करेगा, जिससे हमें स्थिर विकास हासिल करने में मदद मिलेगी। हमारे ऑटो व्यवसाय के EBITDA सकारात्मक होने के लक्ष्य के साथ, यह सर्टिफिकेशन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत उत्प्रेरक का काम करता है।

क्या है PLI सर्टिफिकेशन?

यह भारत सरकार द्वारा कंपनियों को कुछ उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि के लिए दी जाने वाली वित्तीय प्रोत्साहन योजना का हिस्सा है। इसका मुख्य लक्ष्य भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, आयात कम करना, और रोजगार के अवसर पैदा करना है। जब कोई कंपनी, जैसे ओला इलेक्ट्रिक, अपनी उत्पादन प्रक्रिया को सरकार की इस योजना के नियमों के अनुसार ढालती है, और उसके उत्पाद पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो उसे यह सर्टिफिकेशन मिलता है। यह सर्टिफिकेशन मिलने के बाद, कंपनी को सरकार से वित्तीय लाभ या इंसेंटिव मिलता है, जिससे उसे मुनाफा बढ़ाने में मदद मिलती है। यह ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, और सोलर पीवी निर्माण जैसे कई सेक्टरों के लिए उपलब्ध है।

नई रेनॉल्ट डस्टर की कीमतों का जल्द होगा एलान, जानें क्या होंगे खास फीचर्स

रेनॉल्ट जल्द ही भारत में नई Duster SUV लॉन्च करने वाली है। इसका निर्माण चेन्नई में होगा और इसे 2025 के अंत तक पेश किया जा सकता है। शुरुआत में यह पेट्रोल इंजन के साथ आएगी जिसके बाद हाइब्रिड वर्जन लॉन्च किया जाएगा। नई डस्टर में कई आधुनिक फीचर्स होंगे और इसकी कीमत 10 लाख से 17 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। हाल ही में Renault ने भारतीय बाजार में नई ट्राइबर और अपग्रेडेड काइगर को लॉन्च कियाय है। अब कंपनी अपनी सबसे पॉपुलर SUV, Renault Duster की कीमत की घोषणा को पक्की कर दी है। इसकी कीमतों का एलान आने वाले महीनों में किया जाएगा। इसे पहले से ज्यादा कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लेकर आया जाएगा, जो इसे बाकी SUV से अलग बनाने का काम करेगा।

नई Duster लॉन्च की टाइमलाइन हुई कन्फर्म

तीसरी जनरेशन की Renault Duster SUV का प्रोडक्शन सितंबर 2025 से शुरू होगा। इसका निर्माण Renault के चेन्नई में स्थित प्लांट में होगा। हाल ही में Renault ने निसान इंडिया से 51 प्रतिशन हिस्सेदार खरीदकर इस प्लांट का पुरा कंट्रोल अपने पास ले लिया है।

उम्मीद है कि भारत के लिए नई-जनरेशन Renault Duster को फेस्टिव सीजन यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 के आसपास पेश किया जा सकता है। कीमतों का एलान इस साल के अंत तक होने की उम्मीद है, जबकि इसकी डिलीवरी जनवरी 2026 से शुरू हो सकती है।

पहले पेट्रोल, फिर हाइब्रिड में होगी लॉन्च

नई-जनरेशन Renault Duster को शुरुआत में केवल पेट्रोल इंजन के साथ लेकर आया जाएगा। इसके पेट्रोल इंजन को लॉन्च करने के कुछ महीनों के बाद हाइब्रिड वर्जन को लाया जाएगा। इसके हाइब्रिड वर्जन को साल 2026 के अंत या 2027 के शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। उम्मीद है कि यह एसयूवी 1.3-लीटर, 4-सिलेंडर, टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 151bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। ट्रांसमिशन ऑप्शन के रूप में 6-स्पीड मैनुअल और एक ड्युअल-क्लच ऑटोमैटिक दिया जा सकता है। इसके बेस मॉडल में 1.5-लीटर NA पेट्रोल या 1.0-लीटर 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है।

नई-जनरेशन Renault Duster को कंपनी के नए CMF-B मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर डिजाइन और डेवलप किया गया है। यह एसयूवी आधुनिक इंटीरियर और कई सुविधा फीचर्स के साथ आएगी। इसमें 0.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट (वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ), एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। सेफ्टी के लिए लेवल 2 ADAS तकनीक, 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, 6 एयरबैग, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, और हिल लॉन्च/डिसेंट कंट्रोल दिए जा सकते हैं।

कितनी होगी कीमत?

नई-जनरेशन Renault Duster को 10 लाख रुपये से 17 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत के बीच लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय बाजार में इसका मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट मुकाबला, Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara से देखने के लिए मिलेगा।

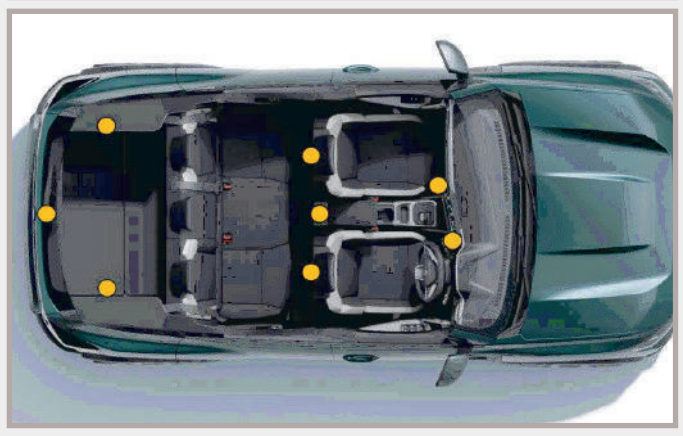

विज्ञान आज हमें बताता है कि मस्तिष्क अत्यधिक अनुकूलनीय है कि हम कितनी तेजी से समझ और नई जानकारी बनाए रखने

विजय गर्ग

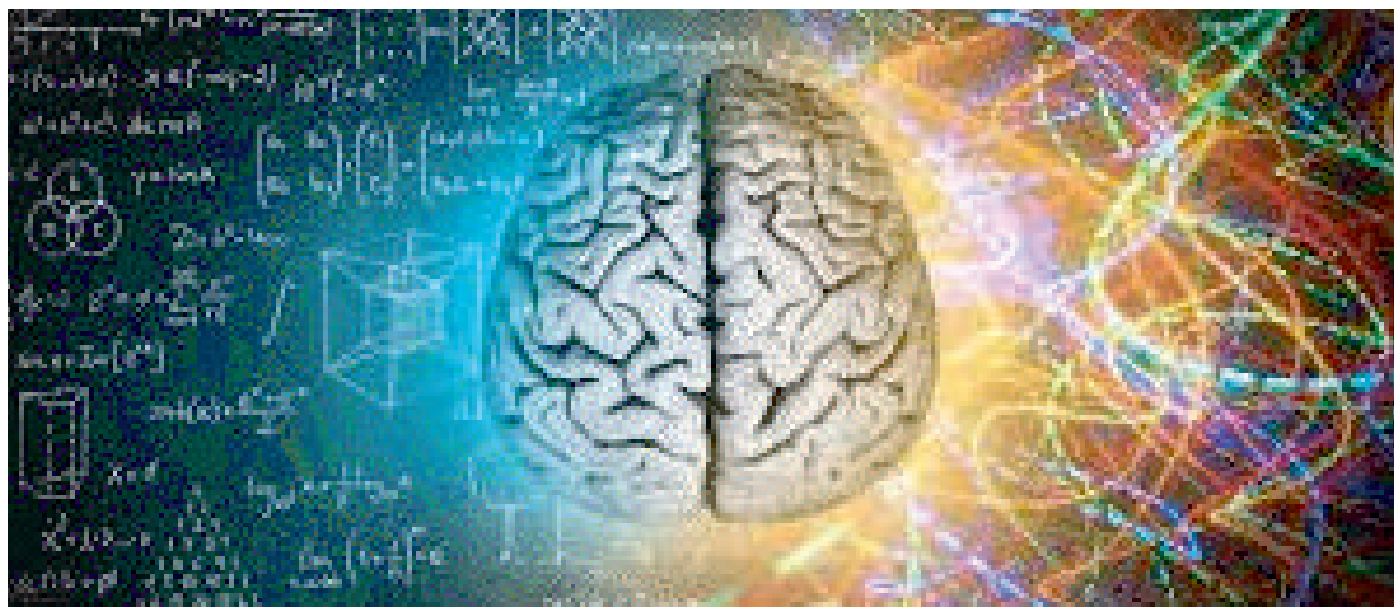

वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि तेजी से सीखना कठिन अध्ययन के बारे में नहीं बल्कि सही तरीकों का उपयोग करने के बारे में है। रिक्ति पुनरावृत्ति, सक्रिय याद और अच्छी नींद जैसी तकनीकों को लागू करके, कोई भी अपने मस्तिष्क को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने के लिए प्रशिक्षित कर सकता है। इन छोटे कदमों से एक बड़ा फर्क पड़ता है कि ज्ञान कितनी जल्दी स्थायी समझ में बदल जाता है।

विज्ञान आज हमें बताता है कि मस्तिष्क अत्यधिक अनुकूलनीय है कि हम कितनी तेजी से समझ और नई जानकारी बनाए रखने

सीखना केवल अधिक घंटों में डालने के बारे में नहीं है, यह होशियार सीखने के बारे में है। विज्ञान आज हमें बताता है कि मस्तिष्क अत्यधिक अनुकूलनीय है, और आदतों में छोटे परिवर्तन काफी सुधार कर सकते है कितनी तेजी से हम समझ और नई जानकारी बनाए रखने।

यहां सात तकनीकें हैं, जो अनुसंधान में निहित हैं, जो आपको अपनी सीखने की गति को तेज करने में मदद कर सकती हैं।

1अंतराल पुनरावृत्ति

सभी को एक बार में क्रैमिंग करने के बजाय, अपने अध्ययन सत्रों को दिनों में वितरित करें। मनोवैज्ञानिक इसे ₹अंतर प्रभाव₹ कहते हैं अंतराल पर सामग्री का फिर से आना स्मृति लिंक को मजबूत करता है और सहज याद करता है।

2.।सीखने के लिए सिखाने

किसी और को एक अवधारणा समझाना सबसे शक्तिशाली सीखने के उपकरणों में से एक है। जब आप सिखाते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में जानकारी को पुनर्गठित करते हैं, अंतराल की पहचान करते हैं, और समझ को गहरा करते हैं। यहां तक कि एक काल्पनिक कक्षा को पढ़ाने से भी चमत्कार हो सकता है।

3। सक्रिय रिकॉर्ड अभ्यास बस नोट्स को फिर से पढ़ना काम नहीं करता है। इसके बजाय, अपनी पुस्तक को बंद करें और स्मृति से प्रमुख बिंदुओं को याद करने का प्रयास करें। यह सक्रिय संघर्ष तंत्रिका मार्गों को मजबूत करता है और दीर्घकालिक प्रतिधारण बनाता है।

4। साक्षात्कार के विषय घंटों तक एक विषय पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, विषयों को मिलाएं। उदाहरण के लिए, गणित का एक छात्र एक सत्र में बीजगणित, ज्यामिति और पथरी को जोड़ सकता है। इंटरलेविंग नामक यह विधि अनुकूलनशीलता में सुधार करती है और समस्या को सुलझाने के कौशल को तेज करती है।

5.। दृश्य और स्थानिक स्मृति का उपयोग हमारे दिमाग छवियों के लिए वायर्ड हैं। अमूर्त अवधारणाओं को मन के नक्शे, आरेख या दृश्य कहानियों में बदलना उन्हें पुनः प्राप्त करना आसान बनाता है। प्राचीन काल से इस्तेमाल की जाने वाली 'मेमोरी पैलेस' तकनीक अब भी बेहद कारगर साबित होती है.

6।नींद और सांत्वना

नींद के बिना सीखना अधूरा है। गहरी नींद के दौरान, मस्तिष्क नई यादों को मजबूत करता है और अनावश्यक अव्यवस्था को दूर करता है। अध्ययन के बाद 20 मिनट की झपकी पढ़ने के एक और घंटे की तुलना में प्रतिधारण को बेहतर बना सकती है।

7.।जानकारी भेजना मस्तिष्क पैटर्न को याद करता है, अंतहीन विवरण नहीं। जानकारी को सार्थक “chunks” में समूहीकृत करना, जैसे किसी फ़ोन नंबर को खंडों में तोड़ना, संज्ञानात्मक भार को कम करता है और समझ को गति देता है।

फास्ट लर्निंग एक जादू की चाल नहीं है; यह स्वाभाविक रूप से मस्तिष्क कैसे काम करता है के साथ संरेखित करने के बारे में है। इन सात तकनीकों का अभ्यास करके, आप अध्ययन के समय को एक कुशल, मस्तिष्क के अनुकूल प्रक्रिया में बदल देते हैं।

एक बार जो भारी लग रहा था वह प्रबंधनीय हो जाता है, और सीखना एक सक्रिय, पुरस्कृत यात्रा में बदल जाता है।

वैज्ञानिक ग्रहों या सितारों के तापमान का निर्धारण कैसे करते हैं

विजय गर्ग

वैज्ञानिक मुख्य रूप से उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का विश्लेषण करके दूर के ग्रहों और सितारों के तापमान का निर्धारण करते हैं। चूंकि इन खगोलीय पिंडों पर शारीरिक रूप से थर्मामीटर लगाना असंभव है, खगोलविद काले शरीर के विकिरण के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, जो बताता है कि पूर्ण शून्य से ऊपर के तापमान वाली सभी वस्तुएं विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन करती हैं। सितारों के तापमान को मापना एक तारे का तापमान एक महत्वपूर्ण संपत्ति है जो इसके रंग, चमक और वर्णक्रमीय प्रकार को निर्धारित करती है। खगोलविद कुछ मुख्य तरीकों का उपयोग करते हैं:

रंग-तापमान संबंधः एक तारे का रंग सीधे इसकी सतह के तापमान से संबंधित होता है। सबसे गर्म सितारे नीले-सफेद दिखाई देते हैं, जबकि सबसे अच्छे सितारे लाल होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक स्टार का शिखर उत्सर्जन तरंग दैर्ध्य Wien के विस्थापन कानून के अनुसार तापमान के साथ बदलता है। विभिन्न रंग फिल्टर (फोटोमेट्री नामक एक प्रक्रिया) के माध्यम से एक स्टार की चमक को मापने से, वैज्ञानिक इसके चरम तरंग दैर्ध्य का निर्धारण कर सकते हैं और परिणामस्वरूप, इसका तापमान। टी प्रोप्टो फ्राक {1} {\lambda_ {अधिकतम}} जहां T तापमान है और lambda_ {max} उत्सर्जित विकिरण का चरम तरंग दैर्ध्य है।

स्पेक्ट्रोस्कोपीः एक अधिक सटीक विधि में एक स्टार के स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करना शामिल है, जो विभिन्न तरंग दैर्ध्य में प्रकाश की तीव्रता का वितरण है। हॉटर सितारों में छोटे, ब्लूर तरंग दैर्ध्य में अपने स्पेक्ट्रम में एक चोटी होती है, जबकि कूलर तारे लंबे समय तक चरम पर होते हैं, रेडर तरंग दैर्ध्य। इसके अलावा, किसी तारे के वायुमंडल में विभिन्न रासायनिक तत्वों से अवशोषण लाइनों की उपस्थिति और ताकत इसके तापमान पर अत्यधिक निर्भर है। इन वर्णक्रमीय रेखाओं का अध्ययन करके, खगोलविद एक तारे को सही ढंग से वर्गीकृत कर सकते हैं और इसके तापमान का निर्धारण कर सकते हैं। ग्रहों के तापमान को मापने किसी ग्रह का तापमान निर्धारित करना थोड़ा अधिक जटिल है क्योंकि ग्रह अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। इसके बजाय, वे या तो अपने मेजबान स्टार से प्रकाश को दर्शाते हैं या अपने स्वयं के थर्मल विकिरण (गर्मी) का उत्सर्जन करते हैं।

थर्मल उत्सर्जनः ग्रह, सभी वस्तुओं की तरह, अवरक्त प्रकाश के रूप में गर्मी विकीर्ण करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे अंतरिक्ष दूरबीन संवेदनशील उपकरणों से लैस हैं जो इस मंद अवरक्त विकिरण का पता लगा सकते हैं। इस उत्सर्जित गर्मी की मात्रा और तरंग दैर्ध्य को मापकर, वैज्ञानिक ग्रह के तापमान की गणना कर सकते हैं, यह मानते हुए कि यह एक काले शरीर की तरह व्यवहार करता है। यह विधि एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल और सतहों का अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।

संतुलन तापमान मॉडलः उन ग्रहों के लिए जिनके पास एक महत्वपूर्ण वातावरण नहीं है, वैज्ञानिक अपने तारे से प्राप्त ऊर्जा और अंतरिक्ष में वापस आने वाली ऊर्जा के बीच संतुलन पर विचार करके किसी ग्रह के तापमान का अनुमान लगा सकते हैं। यह गणना एक सरलीकृत मॉडल है जो स्टार की चमक, तारे से ग्रह की दूरी और इसकी परावर्तन (एल्बेडो) को ध्यान में रखता है। जबकि हमेशा पूरी तरह से सटीक नहीं होता है, यह किसी ग्रह के तापमान का एक अच्छा पहला अनुमान प्रदान करता है।

प्राकृतिक आपदा में अद्र्ध सैनिक बल

गृह मंत्री ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया जाएगा। 2019 से 2025 तक के बीच 1025 नक्सली मारे गए हैं और 6983 गिरफ्तार हो चुके हैं। यह संख्या बताती है कि नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। गृह मंत्री के दृढ़ संकल्प से यह संभव हो रहा है और सरकार इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेकर आर्थिक संसाधन में कोई कमी नहीं होने दे रही है। इसके साथ-साथ आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए भी कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं जो देखने में आ रहे हैं। इसके लिए एनआईए का दायरा बढ़ाया गया है और कानून भी सख्त किए गए हैं। पीएफआई, हुर्रियत जैसे संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं जिससे आतंक के मामलों में कमी आई है। लेकिन सिर्फ सख्ती या सुरक्षा बलों की ताकत से कई बार समस्याएं नहीं सुलझती हैं और इसलिए शाह ने गृह मंत्रालय को राज्यों के साथ मिलकर विकास तथा पुनर्वास की कई योजनाओं पर काम करने की व्यवस्था की जिसका बढिया परिणाम दिख रहा है

-मधुरेंद्र सिन्हा

इस समय देश के हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा आई हुई है। पहाड़ों में कहीं भूस्खलन तो कहीं बादल फटना। दर्जनों लोग काल कलवित हो गए हैं और हजारों मकान तथा दर्जनों बस्तियां दब गई हैं। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में प्रकृति का प्रकोप कुछ ज्यादा ही है। इन राज्यों में तुरंत राहत की व्यवस्था करना बेहद कठिन है, क्योंकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचना ही बेहद कठिन होता है। रास्ते कट जाते हैं, पहाड़ी नदियां उफन जाती हैं और आसपास से कोई मदद नहीं मिल पाती है। लेकिन अब जिस तरह से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ समर्पित भाव से उन इलाकों में राहत कार्य करने में जुटा हुआ है, उसे देखकर आशा की किरण जाग उठी है। इस बल का गठन ही प्राकृतिक आपदाओं और खतरनाक परिस्थितियों से निबटने के लिए किया गया था। पिछले पांच-छह वर्षों में इसने जबरदस्त तरीके से काम किया और लोगों में इतना विश्वास पैदा कर दिया कि अब विपदा आते ही इसे बुलाया जाता है और इसके जवान तुरंत आकर राहत कार्यों में लग जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है कि ये कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी काम करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है इनका समर्पण भाव। इस समय इनकी टुकडियां न केवल हिमाचल, उत्तराखंड में राहत कार्य में दिन-रात जुटी हुई हैं बल्कि बिहार की बाढ़ में भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इसने अब तक डेढ़ लाख लोगों की जान बचाई है और लाखों फंसे लोगों को निकाला है। गृह मंत्रालय ने इसे पूरी तरह से साजो-सामान से लैस कर दिया है जिससे राहत कार्यों में तेजी आ सके। मंत्रालय ने 2024-25 में एसडीआरएफ के लिए 20264 करोड़ रुपए आवंटित किए और एनडीआरएफ के लिए 5160 करोड़ रुपए आवंटित किए जो एक कीर्तिमान है और जिसके परिणाम देखने में आ रहे हैं।

मार्च 2021 में एक नया अलर्ट सिस्टम जारी किया गया जिससे अब संगठन पहले ही खतरे की संभावना बता देता है जिससे लोग सावधान हो जाएं। इसका उदाहरण है कि इसने अब तक 631.1 करोड़ अलर्ट मैसेज भेजे हैं और बेशकीमती जिंदगियां बचाई हैं। इसका कार्य सिर्फ भारत ही नहीं था, बल्कि विदेशों में भी रहा। हमने देखा कि कैसे तुर्की में इसने समर्पित भाव से इनसानियत की रक्षा की। गृह मंत्रालय ने गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में न केवल एनडीआरएफ बल्कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, कोस्ट गार्ड को पूरी शक्तियां दीं, बल्कि संसाधन तथा पूरे कानूनी अधिकार भी दिए। इसके ठोस परिणाम साफ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के छह साल पूरे कर लिए हैं और इस दौरान देश में अर्ध सैनिक बलों को बढ़ावा देकर कश्मीर में धारा 370 हटाने से लेकर नक्सलवाद के लगभग खात्मे तक का काम कर दिखाया। उनकी सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाइयां भी दीं। कश्मीर में सुरक्षा बलों की त्वरित और दीर्घकालीन कार्रवाई से 2019 से 2025 तक के बीच हिंसक घटनाओं में 2004-09 के बीच 86 फीसदी की कमी आई है। कश्मीर के अलावा मध्य तथा पूर्व भारत में नक्सली हिंसा पर लगाम तो लगी ही है, उनके बड़े लीडर या तो मारे गए हैं या समर्पण कर चुके हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2009 से 2024 के बीच नक्सली हिंसा की वजह से होने वाली मौतों में उल्लेखनीय कमी आई है। पिछले छह सालों में यह गिरकर 600 तक आ गई है, जबकि 2009 से 2014 तक 5225 थी।

नक्सलियों के खिलाफ अर्ध सैनिक बलों का अभियान इस समय इतना जबरदस्त है कि देश के छह जिले ही अब नक्सल हिंसा से प्रभावित रह गए हैं। इसलिए ही गृह मंत्री ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया जाएगा। 2019 से 2025 तक के बीच 1025 नक्सली मारे गए हैं और 6983 गिरफ्तार हो चुके हैं। यह संख्या बताती है कि नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। गृह मंत्री के दृढ़ संकल्प से यह संभव हो रहा है और सरकार इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेकर आर्थिक संसाधन में कोई कमी नहीं होने दे रही है। इसके साथ-साथ आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए भी कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं जो देखने में आ रहे हैं। इसके लिए एनआईए का दायरा बढ़ाया गया है और कानून भी सख्त किए गए हैं। पीएफआई, हुर्रियत जैसे संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं जिससे आतंक के मामलों में कमी आई है। लेकिन सिर्फ सख्ती या सुरक्षा बलों की ताकत से कई बार समस्याएं नहीं सुलझती हैं और इसलिए शाह ने गृह मंत्रालय को राज्यों के साथ मिलकर विकास तथा पुनर्वास की कई योजनाओं पर काम करने की व्यवस्था की जिसका बढिया परिणाम दिख रहा है। विकास एक ऐसा माध्यम है जिससे हिंसा तथा अराजकता पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसे ही ध्यान में रखकर पूर्वोत्तर के राज्यों में कई योजनाएं बनाई गई हैं।

वहां शांति प्रक्रिया के तहत छह वर्षों में 12 शांति समझौते हुए, जिसके कारण से स्थिति में अभूतपूर्व सुधार आया। वहां अफस्पा को तेजी से हटाया जा रहा है और दो राज्यों त्रिपुरा तथा मेघालय में यह पूरी तरह से हटा दिया गया है तथा अन्य राज्यों के थोड़े से हिस्से में ही यह लागू है। साइबर क्राइम देश के सामने एक चुनौती की तरह है और इसका मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन गृह मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाकर इस दिशा में सख्त कार्रवाई हो रही है। इसके लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑरडिनेशन सेंटर (14 सी) बनाया गया है। यह साइबर क्राइम से निबटने के लिए आधुनिकतम टेक्नोलॉजी से लैस है और इसने इन अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है और अभी भी कर रहा है। साइबर क्राइम के अलावा देश में ड्रग के खतरों के खिलाफ कई कदम उठाए गए हैं जिनमें काफी सफलता मिली है। पड़ोसी देश पाकिस्तान से ड्रग की खेप न केवल पकड़ी जा रही है, बल्कि कुछ अन्य देशों की सीमाओं पर भी सख्ती की जा रही है। गृह मंत्रालय, रसायन मंत्रालय, औषधि मंत्रालय के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रहा है। इनमें सफलता भी मिल रही है। इस तरह अद्र्ध सैनिक बलों की भूमिका सराहनीय है।

क्वांटम आयु

‘क्वांटम आयु₹ एक शब्द है जिसका उपयोग क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों को समझने, नियंत्रित करने और लागू करने की हमारी क्षमता से प्रेरित तकनीकी उन्नति के एक नए युग का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जबकि क्वांटम यांत्रिकी की सैद्धांतिक नींव एक सदी पहले रखी गई थी, वर्तमान ‘क्वांटम आयु’ को विभिन्न क्षेत्रों को बदलने की क्षमता के साथ व्यावहारिक क्वांटम प्रौद्योगिकियों के उद्भव द्वारा परिभाषित किया गया है। क्वांटम आयु की प्रमुख अवधारणाएँ क्वांटम आयु उप-परमाणु दुनिया के अद्वितीय और अक्सर नकली गुणों पर बनाई गई है, जिसमें शामिल हैं:

सुपरपोजिशनः एक शास्त्रीय बिट के विपरीत, जो या तो 0 या 1 हो सकता है, एक क्वांटम बिट (क्विबिट) एक साथ दोनों राज्यों के सुपरपोजिशन में मौजूद हो सकता है। यह क्वांटम कंप्यूटर को समानांतर में जानकारी की एक विशाल राशि को संसाधित करने की अनुमति देता है।

उलझनाः यह एक ऐसी घटना है जहां दो या दो से अधिक क्यूबिट्स को इस तरह से जोड़ा जाता है कि एक की स्थिति तुरंत दूसरों की स्थिति को प्रभावित करती है, चाहे वे कितने भी अलग क्यों न हों। यह ‘दूरी पर डरावना कार्रवाई’, जैसा कि आइंस्टीन ने कहा था, क्वांटम संचार और गणना के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है।

मात्राकरणः यह विचार कि भौतिक गुण, जैसे ऊर्जा, केवल असतत, अविभाज्य पैकेट या ‘क्वांटा’ में मौजूद हो सकते हैं। यह 1900 में मैक्स प्लैंक द्वारा शुरू की गई एक मूलभूत अवधारणा थी। क्वांटम प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्र क्वांटम आयु केवल कंप्यूटिंग के बारे में नहीं है। इसमें कई परस्पर जुड़े क्षेत्र शामिल हैं:

क्वांटम कम्प्यूटिंगः यह सबसे प्रसिद्ध पहलू है। क्वांटम कंप्यूटर में उन समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है जो सबसे शक्तिशाली शास्त्रीय सुपर कंप्यूटर के लिए भी अचूक हैं। यह दवा की खोज, भौतिक विज्ञान, वित्तीय मॉडलिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है।

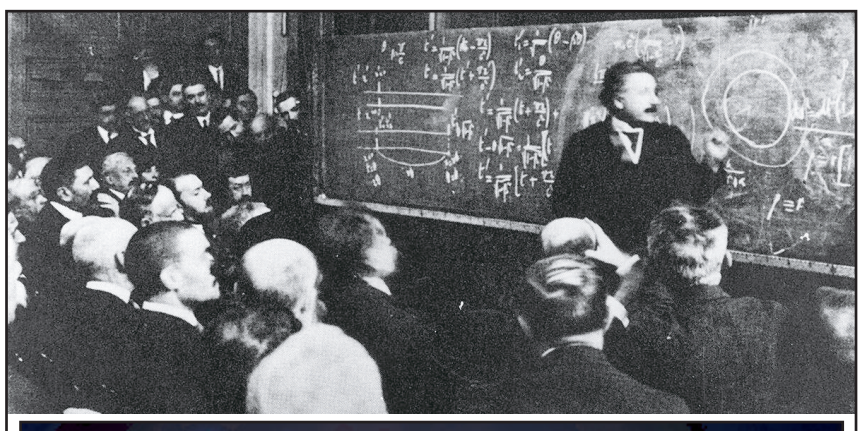

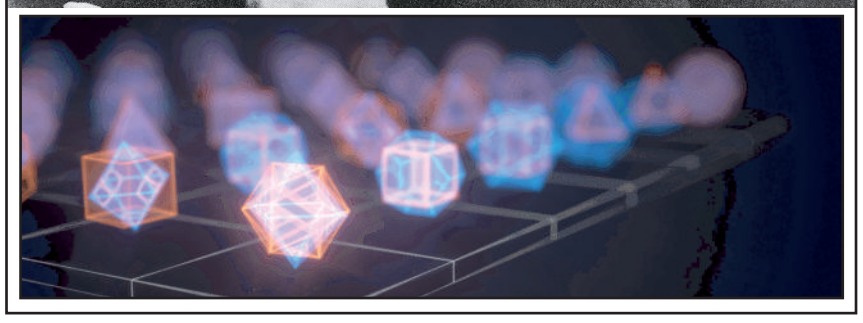

क्वांटम संचारः यह क्षेत्र अल्ट्रा-सुरक्षित संचार नेटवर्क बनाने पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए, क्वांटम कुंजी वितरण (QKD), भौतिकी के कानूनों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि किसी प्रेषित कुंजी पर कोई भी ईव्सड्रॉपिंग प्रयास तुरंत पता लगाने योग्य है।

क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजीः क्वांटम सिस्टम की चरम संवेदनशीलता का लाभ उठाकर, क्वांटम सेंसर माप में सटीकता के अभूतपूर्व स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। अनुप्रयोग चिकित्सा इमेजिंग और नेविगेशन से लेकर मौलिक भौतिकी अनुसंधान तक हैं। ऐतिहासिक प्रसंग क्वांटम एज के लिए सैद्धांतिक आधार 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में रखा गया था। मुख्य मील के पत्थर में शामिल हैं:

1900: मैक्स प्लैंक काले शरीर विकिरण समस्या को हल करने के लिए ऊर्जा क्वांटा की अवधारणा का परिचय देता है।

1905: अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह प्रस्ताव देकर फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या की कि प्रकाश असतत कणों (फोटॉन) से बना है।

1920 के दशकः क्वांटम यांत्रिकी का औपचारिक सिद्धांत नील्स बोहर, वर्नर हाइजेनबर्ग, इरविन श्रोडिंगर और अन्य सहित शानदार भौतिकविदों की एक पीढ़ी द्वारा विकसित किया गया है। जबकि एक तकनीकी युग के रूप में ‘क्वांटम आयु’ एक और हाल ही में विकास है, क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों कई प्रौद्योगिकियों हम आज उपयोग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे ट्रांजिस्टर, लेजर, और सौर कोशिकाओं। चुनौतियां और भविष्य क्वांटम एज अभी भी अपने शुरुआती चरणों में है। महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें शामिल हैं:

तकनीकी सीमाएं: एक स्थिर और स्केलेबल क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण बेहद मुश्किल है। क्यूबिट्स अपने पर्यावरण से नाजुक और आसानी से बाधित होते हैं, जिससे त्रुटियां होती हैं।

कार्यबल की कमीः क्वांटम भौतिकी, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ एक कुशल कार्यबल की बढ़ती आवश्यकता है।

साइबर सुरक्षा जोखिमः जबकि क्वांटम संचार सुरक्षा के एक नए स्तर का वादा करता है, क्वांटम कंप्यूटर की शक्ति भी आज इस्तेमाल एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम के कई तोड़ सकता है, डिजिटल सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा । इन चुनौतियों के बावजूद, क्वांटम तकनीक की क्षमता विशाल है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्वांटम आयु नवाचार के एक नए युग में प्रवेश करेगी, अनुप्रयोगों के साथ जो दवा और वित्त से लेकर परिवहन और राष्ट्रीय सुरक्षा तक सब कुछ बदल सकते हैं। यह अन्वेषण, आविष्कार और खोज की अवधि है जो सूचना युग के रूप में परिवर्तनकारी होने का वादा करती है जो इससे पहले थी।

शोध की विश्वसनीयता का संकट

विजय गर्ग

वैज्ञानिक जर्नलों का मूल उद्देश्य है- संबंधित विषय में रुचि रखने वाले पाठकों को नए शोधों और अध्ययनों की सटीक, समकक्ष-समीक्षित (पीयर रिव्यूड) रिपोर्ट प्रदान करना, लेकिन हाल में 'प्रोसीडिंग्स आफ नेशनल एकेडमी आफ साइंसेज' (पीएनएएस) में प्रकाशित एक सांख्यिकीय विश्लेषण के अनुसार वैज्ञानिक साहित्य में धोखाधड़ीपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान से उत्पन्न नकली नतीजे तेजी से घुस रहे। हैं, जिससे यह उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो रहा है। विश्लेषणकर्ताओं का निष्कर्ष है कि वैज्ञानिक अनुसंधानों में धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर होती है और वह तेजी से बढ़ रही है। ये निष्कर्ष 70,000 जर्नलों में प्रकाशित 50 लाख से अधिक वैज्ञानिक शोधपत्रों के विश्लेषण से सामने आए हैं। शोधकर्ताओं को ऐसे संदिग्ध संगठनों के प्रमाण मिले हैं, जो औद्योगिक स्तर पर नकली या निम्न- गुणवत्ता वाले शोधपत्र तैयार कर रहे हैं। और उनका उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे वैज्ञानिक शोध की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। नार्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के डाटा विज्ञानी और पीएनएएस जर्नल में प्रकाशित हालिया अध्ययन के लेखक लुइस ए. नून्स अमरल का कहना है कि 'अगर इन खतरनाक प्रवृत्तियों को नहीं रोका गया, तो वर्तमान वैज्ञानिक तंत्र नष्ट हो जाएगा !'

पिछली कुछ शताब्दियों में विज्ञान ने अभूतपूर्व प्रगति की है, केवल इसलिए क्योंकि विज्ञानियों की नई पीढ़ियां पिछली पीढ़ियों की उपलब्धियों के बारे में पढ़ सकीं। हर बार जब कोई नया शोधपत्र प्रकाशित होता है, तो बाकी विज्ञानी उस खोज का अध्ययन कर सकते हैं और अपनी खोजों को आगे बढ़ाने के तरीके के बारे में सोच सकते हैं। उल्लेखनीय है कि विज्ञान दूसरों के काम पर भरोसा करने पर निर्भर करता है, इसलिए शोधकर्ताओं को हर चीज दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां वैज्ञानिक शोधपत्रों की संख्या प्रत्येक 15 वर्ष में दोगुनी होती है, वहीं धोखाधड़ीपूर्ण लेखों की संख्या मात्र 1.5 साल में दोगुनी हो रही है। यह स्थिति न सिर्फ बेहद चिंताजनक है, बल्कि विज्ञानी समुदाय की साख को भी गहरी चोट पहुंचा रही है। धोखाधड़ी केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं हो रही, बल्कि इसके पीछे पेपर मिलों और ब्रोकरेज फर्मों जैसी समन्वित संस्थाओं का नेटवर्क सक्रिय है। ये संस्थाएं नकली शोधपत्र तैयार करती हैं, जिनमें सावधानी से गढ़े हुए आंकड़े और झूठे प्रयोग सम्मिलित होते हैं। अक्सर एआइ का सहारा लेकर ये पाठ्य तैयार किए जाते हैं। फिर उसे इच्छुक अकादमिक लोगों को बेचा जाता है, जो अपनी प्रकाशन संख्या बढ़ाना चाहते हैं ।

यह स्थिति मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए कठोर निगरानी और पारदर्शी समीक्षा प्रक्रिया की आवश्यकता है। नहीं तो, विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति 'उसकी विश्वसनीयता' पर ही प्रश्न चिह्न खड़ा हो जाएगा !

स्पेस जंक: भविष्य के मिशनों पर मंडराता खतरा

आज हर कहीं प्रदूषण का बोलबाला है और अब केवल धरती ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष भी प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। इसे स्पेस डेब्रिस या अंतरिक्ष कचरा कहा जाता है। पाठकों को बताता चलूं कि जब उपग्रह (सैटेलाइट), रॉकेट, अंतरिक्ष यान आदि अपने कार्य पूरे करने के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं या टूट-फूट जाते हैं, तो उनके अवशेष अंतरिक्ष में ही तैरते रहते हैं और यही कचरा या मलबा अंतरिक्ष प्रदूषण कहलाता है।सच तो यह है कि निष्क्रिय उपग्रह,जिनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, अंतरिक्ष कचरा पैदा करते हैं। अनेक बार उपग्रहों या मलबे की आपसी टक्कर से भी छोटे-छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। ईंधन खत्म होने के बाद भी रॉकेट के टुकड़े अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं।अंतरिक्ष मिशनों की असफलता या यूं कहें कि फेल हुए यान और उनके हिस्से भी अंतरिक्ष कचरे का बड़ा कारण बनते हैं। अंतरिक्ष में कचरा फैलने का दुष्परिणाम यह होता है कि इससे जहां एक ओर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले नए उपग्रहों और स्पेस स्टेशनों के लिए खतरा पैदा हो जाता है, वहीं दूसरी ओर स्पेस मिशनों की लागत और जोखिम भी इससे बढ़ जाता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि अंतरिक्ष में बन रहे कचरे के बादल जीपीएस, संचार और मौसम के पूर्वानुमान सहित अंतरिक्ष आधारित तकनीकों पर निर्भर उद्योगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इतना ही नहीं, पृथ्वी के वातावरण में गिरते मलबे से जन-जीवन को भी खतरा पैदा होता है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि जब अंतरिक्ष में मलबा इतना बढ़ जाए कि उपग्रह भेजना असंभव हो जाए, तो इसे 'केसलर सिंड्रोम' के नाम जाना जाता है। आज मानव धरती तो धरती, अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए नित नए शोध, अनुप्रयोग कर रहा है, लेकिन आज दुनिया भर से लॉन्च होने वाले बड़े सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रॉकेट और उनके ईंधन धरती के साथ ही अंतरिक्ष को भी लगातार प्रदूषित कर रहे हैं, यह बहुत ही चिंताजनक है।गौरतलब है कि लंदन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही के अपने अध्ययन में इसका खुलासा किया है और इस पर अपनी चिंताएं जताई है।यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन(यूसीएल) के प्रमुख शोधकर्ता प्रोफ़ेसर एलोइस मराइस और उनकी टीम ने यह पाया कि वर्ष 2023 में 223 तथा वर्ष 2024 में 259 रॉकेट लॉन्च किए गए, और कुल मिलाकर, इनसे 153,000 टन से अधिक ईंधन जलाया गया है। इसके बड़े पर्यावरणीय प्रभाव पड़े हैं। जानकारी के अनुसार इन लॉन्चों और मेगा-कॉन्स्टेलेशन सैटेलाइट्स जैसे स्टार लिंक,वनवेब तथा थाउजेंड सैल्स से सूट और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में तीन गुना बढ़ोतरी देखी गई है।ये प्रदूषक ऊपरी वायुमंडल में लंबे समय तक रहते हैं और सतही स्रोतों की तुलना में 500 गुना अधिक गर्मी फैलाने की क्षमता रखते हैं। बताया गया है कि भविष्य में अमेज़न कुईपर मिशन द्वारा इस्तेमाल होने वाले ठोस ईंधन से ओज़ोन-ध्वंसक क्लोरीन यौगिक निकलेंगे, जो धरती की सुरक्षा परत कहलाने वाली ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विशेषज्ञ इस बात से सहमत है कि इस संकट के हल के लिए तकनीकी नवाचार और सख्त नियम दोनों की जरूरत है। बहरहाल, शोध में यह भी खुलासा हुआ है कि साल 2024 में 2,539 वस्तुएँ वायुमंडल में वापस आकर जल गईं, जिसके कारण 13,500 टन सामग्री वायुमंडल में घुली। इतना ही नहीं, उपग्रह पुनः प्रवेश से रासायनिक प्रदूषण हुआ है। डॉ. कोनोर बार्कर ने पाया कि उपग्रहों और रॉकेट के टुकड़ों के वायुमंडल में जलने से जारी एलुमिनियम और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की मात्रा 2020 की 3.3 बिलियन ग्राम से बढ़कर 2022 में 5.6 बिलियन ग्राम हो गई।प्रोफ़ेसर एलोइस मराइस ने शोध-पत्र में यह दिखाया है कि रॉकेट लॉन्च और अंतरिक्ष कचरा उत्सर्जन ओज़ोन परत की मरम्मत—जिसे मांट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हासिल किया गया था—को प्रभावित कर रहे हैं, और वैश्विक जलवायु को भी बदल रहे हैं। पाठकों को यहां बताता चलूं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन-क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए 1987 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ताकि पृथ्वी की समतापमंडलीय ओजोन परत की रक्षा की जा सके। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ओजोन परत वायुमंडल के स्ट्रैटोस्फीयर (समताप मंडल) में पाई जाती है, जो धरती की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊँचाई पर फैली हुई है। इसमें ओजोन गैस (O_3) के अणु मौजूद होते हैं। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें (अल्ट्रावायलेट रेज) जीव-जंतुओं, पौधों और मनुष्यों के लिए हानिकारक होती हैं। ओजोन परत इन किरणों को सोखकर धरती पर पहुँचने से रोकती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है, जिसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले रसायनों, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसीज), को नियंत्रित करना है। बहरहाल, यह एक कटु सत्य है कि जैसा कि शोधकर्ता ने भी कहा है कि, रॉकेट और सैटेलाइट से वायुमंडल में पहले से कहीं अधिक प्रदूषण फैल रहा है। भले ही यह उत्सर्जन अन्य उद्योगों से कम हो, लेकिन ऊपरी वायुमंडल में यह 500 गुना अधिक नकारात्मक असर यानि प्रदूषण का कारण बन सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि इससे प्रदूषण रोकने वाली परत को नुकसान पहुंच रहा है।उनका यह कहना है कि रॉकेट और सैटेलाइट से पहले कभी इतना प्रदूषण वायुमंडल की ऊपरी परतों में नहीं छोड़ा गया। यह परत प्रदूषण को लंबे समय तक रोककर रखती है। इंसानों ने वायुमंडल की ऊपरी परतों में इतना प्रदूषण पहले कभी नहीं फैलाया। समय रहते यदि इसे नहीं रोका गया, तो पृथ्वी के वायुमंडल पर इसके गंभीर असर दिख सकते हैं। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि वर्तमान में दस देशों के अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा सैटेलाइट मौजूद हैं। गौरतलब है कि इस साल पृथ्वी के ऑर्बिट में सबसे ज्यादा सैटेलाइट की भीड़ है। वहां मौजूद करीब 12,952 सैटेलाइट में से सबसे ज्यादा अमेरिका के हैं।इसके बाद क्रमशः रूस के 1559, चीन के 906, ब्रिटेन के 763, जापान के 203, भारत के 136,फ्रांस के 100, जर्मनी के 82, इटली के 66 और कनाडा के 64 सैटेलाइट मौजूद हैं। हाल फिलहाल, अंतरिक्ष कचरे को लेकर सवाल यह उठता है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है ? तो यहां पाठकों को बताता चलूं कि जब अंतरिक्ष मलबा बनता है तो उसे साफ करने या उसकी निगरानी की जिम्मेदारी उस देश की होती है जिसने वस्तु को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इस क्रम में अंतरिक्ष मलबे पर पहला जुर्माना 2023 में यूएस फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन द्वारा डिश नेटवर्क को जारी किया गया था। पाठकों को यहां यह भी बताता चलूं कि पिछले कुछ दिनों में केन्या समेत अन्य जगहों पर अंतरिक्ष से मलबा गिरने की खबर मिली थी। बहरहाल, जो भी हो, आज तकनीक और नवाचार के इस युग में अंतरिक्ष मलबा एक बड़ा खतरा बनता चला जा रहा है। इसके हमारे वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष मलबे की सफाई के निवारक उपाय अपनाने होंगे। मसलन,इस क्रम में हमें नए उपग्रह और रॉकेट 'एंड आफ लाइफ प्लान' के साथ लॉन्च करना होगा। जैसे ईंधन बचाकर अंत में उन्हें 'ग्रेवयार्ड ओर्बिट' या वायुमंडल में जलाने भेजना होगा। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाने होंगे, ताकि हर स्पेस एजेंसी लॉन्च से पहले मलबा प्रबंधन का रोडमैप दे। छोटे, टिकाऊ और पुनः प्रयोग योग्य रॉकेट तकनीक अपनाई जा सकती है। सक्रिय सफाई तकनीक इस क्रम में काफी उपयोगी साबित हो सकती है।रोबोटिक आर्म / नेट टेक्नोलॉजी-मलबे को पकड़कर पृथ्वी के वायुमंडल में गिराकर जलाना होगा। लेज़र तकनीक भी एक शानदार कदम इस दिशा में साबित हो सकता है। इस तकनीक के अंतर्गत धरती या अंतरिक्ष से शक्तिशाली लेज़र किरणों द्वारा छोटे मलबे की गति बदलकर उसे वायुमंडल में जलाया जाता है।'हरपून सिस्टम' के अंतर्गत बड़े मलबे को पकड़कर खींचकर नीचे लाया जा सकता है। मैग्नेटिक कैचर यानी कि धातु आधारित मलबे को चुंबकीय बल से खींचकर नष्ट किया जा सकता है। हाल फिलहाल, यदि हम यहां पर अंतरिक्ष प्रदूषण को लेकर नए शोध और भविष्य की योजनाओं को लेकर बात करें तो 'क्लियर स्पेस-1(ईएसए प्रोजेक्ट, 2026) यूरोपियन स्पेस एजेंसी पहला मिशन लॉन्च करेगी जो स्पेस मलबे को पकड़कर नष्ट करेगी। एस्ट्रो स्केल (जापान) अंतरिक्ष से सक्रिय मलबा हटाने की तकनीक पर काम कर रही है। इतना ही नहीं,एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो भविष्य में सहयोग करके 'स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करना चाहते हैं। अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिए उपग्रहों का पुनः उपयोग(पुराने सैटेलाइट के पार्ट्स को नए मिशन में उपयोग करना) और रिसाइक्लिंग पर भी ध्यान देना होगा। भविष्य में कक्षा में मौजूद धातुओं को इकट्ठा करके स्पेस रिसाइक्लिंग फैक्ट्रीज बनाई जा सकती हैं। संक्षेप में कहें तो, अंतरिक्ष मलबे की सफाई तीन स्तंभों पर निर्भर है —नया मलबा बनने से रोकना, मौजूदा मलबा हटाना, और रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देना। अंत में, यही कहूंगा कि अगर समय रहते अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे और मलबे पर नियंत्रण किया जाए तो यह मानवता और धरती दोनों के लिए लाभकारी होगा। इससे हमारे उपग्रहों, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा होगी। अगर अंतरिक्ष साफ रहेगा तो नई स्पेस मिशन, शोध कार्य और तकनीकी प्रयोग सुरक्षित और कम लागत में हो सकेंगे। आर्थिक बचत और पृथ्वी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। कहना ग़लत नहीं होगा कि जब अंतरिक्ष सुरक्षित होगा, तो अंतरिक्ष पर्यटन और भविष्य में बसाहट (जैसे चाँद या मंगल पर जीवन) के प्रयास आसान और सुरक्षित होंगे। कुल मिलाकर यह बात कही जा सकती है कि अंतरिक्ष प्रदूषण से बचाव मानव जीवन, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और भविष्य की अंतरिक्ष खोज, हम सभी के लिए अत्यंत लाभकारी है।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

BRICS करेंसी : भविष्य की संभावनाएं

क्या डॉलर के वर्चस्व को झटका लगने वाला है? पूरी दुनिया में अमेरिका की असली ताकत सिर्फ उसकी आर्मी या टेक्नोलॉजी नहीं है। असली हथियार है – US Dollar का वर्चस्व। तेल, गैस, दवाइयाँ, तकनीक, हथियार – हर बड़ा सौदा डॉलर में ही होता है।

IMF और World Bank तक डॉलर को ही आधार मानकर चलते हैं। यही कारण है कि अमेरिका जितना चाहे डॉलर छाप लेता है और पूरी दुनिया उसे अपनाने को मजबूर रहती है।

सही मायने में अमेरिका सिर्फ छापता है और बाकी दुनिया पसीना बहाकर उस Dollar को कमाती है।

BRICS Currency का Concept.

BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) के सामने बड़ा सवाल है – क्या वो मिलकर डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने वाली साझा मुद्रा ला सकते हैं?

स्वरूपः यह नई करेंसी भौतिक (Printed Note) से ज्यादा Digital या Crypto-like फॉर्म में होगी।

बैंकिंगः यह करेंसी डॉलर की तरह ₹हवा में छपने₹ वाली नहीं होगी बल्कि Gold, Rare Metals और Energy Reserves पर आधारित करने की चर्चा है।

नियंत्रणः संभवतः इसका नियमन किसी बहु-देशीय बैंक जैसे BRICS Bank (NDB – New Development Bank) के हाथ में होगा। इसका मुख्यालय Shanghai (China) में है – लेकिन सदस्य देश चाहते हैं कि किसी एक देश का दबदबा न हो।

क्या चीन की Monopoly होगी? यह सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि BRICS में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है और वो अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है लेकिन India, Russia और Brazil साफ कर चुके हैं – अगर यह करेंसी आई तो यह Multi-national Consensus पर चलेगी, किसी एक देश का Private Coin नहीं बनेगी यानी यह ₹Chinese Yuan₹ नहीं होगी बल्कि साझा BRICS Currency होगी।

यह करेंसी काम कैसे करेगी?

शुरुआत में सिर्फ International Trade में तेल, गैस, गेहूं, technology deals – इन्हीं में इसका इस्तेमाल होगा।

धीरे-धीरे Member Countries की कंपनियाँ और Banks आपस में BRICS Currency में Transactions करेंगे।

आम जनता के हाथ में Cash Note या Coin आने की संभावना बहुत कम है।

ज़्यादातर यह Digital Currency के रूप में होगी।

कब तक आने की संभावना है? पिछले 5 साल से चर्चा चल रही है। Russia-Ukraine War और US Sanctions के बाद गति तेज़ हुई है। 2025-26 तक इसका Pilot Project या Limited Trade Usage संभव है।

लेकिन Dollar की पूरी जगह BRICS Currency ले पाए – ऐसा 10-15 साल से पहले मुश्किल है। अगर BRICS Currency सफल हुई तो Dollar की Demand कम होगी। अमेरिका की ₹Print Without Production₹ वाली ताकत टूट जाएगी।

Wall Street की पकड़ ढीली होगी।

Global Trade में ₹Multi-Currency System₹ उभरेगा यानी दुनिया को पहली बार एहसास होगा कि Dollar असल में एक Financial Trap था और हर Trap की एक Expiry Date होती है। इसके Challenges भी कम नहीं हैं:

BRICS देशों के बीच आपसी अविश्वास।

चीन का बढ़ता दबदबा। अलग-अलग देशों की राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताएँ।

Dollar की गहरी जड़े – जो Global Banking System में पहले से हैं।

लेकिन जिस दिन यह करेंसी सचमुच Launch होकर Global Market में Active हो गई – उस दिन साबित हो जाएगा कि Dollar की बादशाहत एक कागज़ी साम्राज्य थी और इतिहास गवाह है – हर साम्राज्य एक दिन गिरता ही है।

शिवानन्द मिश्रा

राजनीतिक सुधार की दिशा में बढ़ते कदम !

डॉ.बालमुकुंद पांडे

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजनीति में संवैधानिक नैतिकता, व्यक्तिगत विवेक, जनता के प्रति जवाबदेही ,संसदीय आचरण, विधायी आचरण एवं व्यक्तिगत ईमानदारी का मानक उच्चतम स्तर का था। राजनीतिक नेतृत्व, संवैधानिक अधिकारी एवं लोकसेवक अपने राजनीतिक एवं नागरिक आभार के प्रति जिम्मेदार होते थे। वह अपने संसदीय एवं विधाई व्यक्तित्व को अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर रखते थे। वह काल दबावविहीन शासकीय कार्यों से ऊपर था। आजादी के शुरुआती दिनों में, राजनीति सेवा का माध्यम था, लोक विश्वास एवं सरलता राजनीति के मानक थे। समय बदलने के साथ राजनीति की प्रकृति बदलने लगी एवं वर्तमान में सत्तालोलुपता , वंशवादी राजनीतिक चिंता, सामान्य इच्छा के बजाय स्वइच्छा की वरीयता एवं नैतिकता के गिरते मूल्य के कारण नैतिकता द्वितीय सोपान पर है। दुर्भाग्य से इस विषय पर संविधान के प्रावधान भी मौन है।

अतीत में राजनीति में शुचिता एवं नैतिकता विवेक ही आधार होते थे जिसको राजनीतिक नेतृत्व एवं संवैधानिक पदाधिकारी अंतःकरण की आवाज मानते थे एवं पदलोलुपता के बजाय स्वच्छ राजनीतिक छवि और इतिहास में अपने व्यक्तित्व को निष्पक्ष रखने के लिए इस्तीफा दे देते थे। तत्कालीन रेल मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी एवं तत्कालीन लोकसभा सदस्य श्री लालकृष्ण आडवाणी ने अपने विवेक एवं अंतःकरण के आत्मतत्व के कारण अपने पदों से इस्तीफा दे दिए। तत्कालीन राजनीति में संवैधानिक नैतिकता, शुचिता एवं सेवा का सफल उदाहरण पेश किए लेकिन समकालीन में ऐसे भी राजनीतिक नेतृत्व एवं संवैधानिक अधिकारी हैं जो कारागार की सजा होने के बावजूद नैतिकताविहीन आचरण किए, राजनीति को सेवा की बजाय भौकाली राजनीतिक संस्कृति एवं सत्तालोलुपता का पर्याय बनाए रहे क्योंकि उन्होंने जमीर, विवेकी प्रज्ञा ,नैतिकता, शुचिता एवं राजनीतिक संस्कृति को ताक पर रख दिया एवं कारागार में निरुद्ध होते हुए अपने शासकीय कार्यों को किया एवं संसदीय चरित्र, मीडिया एवं जनमत को ताक पर रख दिया। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित विभिन्न राज्यों के आठ मंत्रियों ने जेल से अपने शासकीय कार्यों का संचालन किया, इनमें से कम से- कम सात को धन शोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया है जिसमें जमानत के लिए कठोर प्रावधान है। इन नेताओं पर भ्रष्टाचार ,मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी, शराब घोटाले और बंगाल में शारदा चिट फंड एवं शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले हैं।

सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, एवं अन्य मंत्रियों के लिए 30 दिन से अधिक जेल में रहने पर इस्तीफा देना बाध्यकारी होना चाहिए?

हाल ही लोकसभा में 130 वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक अपने आप में एक ऐतिहासिक एवं सुधार की दिशा में विधेयक है। इस विधेयक में प्रावधान है कि किसी गंभीर आरोप में 30 दिन तक जेल में निरूद्ध होने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एवं अन्य मंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा चाहे उसका कद राजनीतिक दल में किसी भी स्तर का हो। इस संशोधन विधेयक में भ्रष्टाचार के मामले में 5 साल की सजा का प्रावधान है। विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 एवं 239 AA में संशोधन की भी सिफारिश कर रहा है।

इस विधेयक का तात्कालिक उद्देश्य शासन एवं शासकीय निकायों में शुचिता एवं आदर्श के मूल्य को स्थापित करना है। सार्वजनिक पदों पर सत्तासीन व्यक्ति अंततोगत्वा जनता के प्रति उत्तरदाई होता है, इसलिए सार्वजनिक संस्थाओं में यह विधेयक विश्वास कायम करने का साधन बनाने का प्रयास किया गया है। समकालीन में लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। जनता का निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति तुलनात्मक रूप से विश्वास कम हो रहा है। लोकतंत्र में नोटा जैसे विकल्पों का आना एवं 75 प्रतिशत तक ही मतदान होना अर्थात लोकतांत्रिक सहभागिता का स्तर शत - प्रतिशत ना होना लोकतांत्रिक समाजीकरण के ह्रास का संकेत है।

उपर्युक्त विधेयक में ,सरकार के मुखिया के रूप में कार्यकारी शक्तियां छीन ली जाएगी लेकिन वह सांसद एवं विधायक की हैसियत से प्रतिनिधित्व करता रहेगा । यह विधेयक लोकतांत्रिक शुचिता एवं संवैधानिक नैतिकता के उन्नयन में महत्वपूर्ण कदम है। यह उस संसदीय परंपरा को मजबूत करेगा कि लोकप्रतिनिधि एवं लोकसेवक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना करते हुए पदों पर आसीन नहीं रह सकते हैं। यह विधेयक ₹ विधि के शासन₹ के उस अवयव को मजबूती प्रदान करेगा कि कलेक्टर एवं चौकीदार समान आभार के व्यक्ति हैं। दोनों के पदों की शुचिता एवं नैतिकता समान मूल्य एवं आदर्श की है। इस विधेयक के द्वारा राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर विधायी नियंत्रण होगा। इससे सुशासन का उन्नयन होगा एवं राजनीतिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास मजबूत होगा। इस विधेयक का लोकतांत्रिक संकेत है कि सार्वजनिक एवं संवैधानिक पद जनता के प्रति जवाबदेही से ही जीवित है।

सवाल यह है कि क्या सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करते हुए विपक्षी दलों को दमन कर सकती है?

लोकतंत्र में सर्वोच्च संविधान है(आर गवई, प्रधान न्यायमूर्ति ,सर्वोच्च न्यायालय)। सरकार के सभी अंग नियंत्रण एवं संतुलन के आधार पर कार्य करते है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री तानाशाह(जनता के प्रति अनुत्तरदायी)नहीं हो सकता हैं क्योंकि वह विधि के शासन, जनमत , मीडिया, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संविधान के द्वारा नियंत्रित है। संसदीय शासन प्रणाली में विपक्ष 'वैकल्पिक सरकार' (अटल बिहारी बाजपेई) आवाज होती है। विपक्ष लोकसभा के द्वारा सरकार एवं सरकारी यांत्रिकी पर नियंत्रण करती है। केंद्रीय जांच एजेंसियां विधि के शासन एवं लोकतांत्रिक शासकीय निकायों के अंतर्गत काम करती हैं। भारत के संविधान के द्वारा सभी लोगों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों को विधायिका एवं कार्यपालिका के द्वारा अतिक्रमण करने पर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में शरण ले सकता है एवं अपने अधिकारों को सुरक्षा कर सकता है। संसदीय शासन प्रणाली में विपक्ष से रचनात्मक सहयोग की आशा की जाती है।

इस विषय पर निम्न सुझाव है:

1. इस विधेयक से सुशासन (Governance) में विश्वास बढ़ेगा ; 2. लोकतांत्रिक तानाशाही पर नियंत्रण होगा ; 3. राजनीतिक संस्कृति एवं राजनीतिक समाजीकरण में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी; 4. सरकार एवं राजनीतिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ेगा;5 लोकतांत्रिक शासकीय व्यवस्था में सहभागिता बढ़ेगी; एवं 6.लोकतंत्र में शुचिता, नैतिकता और राजनीतिक आभार की प्रतिशतता बढ़ेगी।

डॉ.बालमुकुंद पांडे
राष्ट्रीय संगठन सचिव, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना, नई दिल्ली

संसद के हंगामे से लोकतंत्र का मजाक बन रहा है

राजेश कुमार पासी

लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक मंदिर की तरह होती है क्योंकि उसमें जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं । देखा जाए तो एक तरह से जनता ही संसद में बैठती है और वहां से शासन चलाती है । मंदिर पूजा-अर्चना करने की जगह होती है. अगर पूजा सड़कों पर होने लगे तो मंदिर की जरूरत पर सवाल खड़ा हो जाएगा । कुछ ऐसा ही हमारे देश में संसद के साथ हो रहा है । सड़कों पर सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और संसद में हंगामा किया जा रहा है । संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष सरकार से सवाल संसद में करता है और अगर वो उसका जवाब न दे तो सड़कों पर उतर पर उससे जवाब मांगता है । समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि सड़के अगर खामोश रहेंगी तो संसद आवारा हो जाएगी । इसका मतलब है कि जनता को लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए जागना पड़ता है । सवाल यह है कि जब सब कुछ सड़कों पर ही होना शुरू हो जाए ,तब संसद खामोश हो जाएगी ।

आज हमारे देश में कुछ ऐसा ही हो रहा है । संसद सिर्फ हंगामा करने के लिए रह गई है । पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि संसद में कामकाज बंद हो गया है, सिर्फ हंगामा हो रहा है । इस बार संसद में 120 घंटे काम करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन लोकसभा में सिर्फ 37 घंटे ही काम हुआ जबकि दूसरी तरफ राज्यसभा में 120 घंटे की जगह सिर्फ 47 घंटे काम हुआ है । इस तरह देखा जाए तो लोकसभा ने 120 में से 83 घंटे बर्बाद कर दिए तो दूसरी तरफ राज्यसभा ने 73 घंटे बर्बाद किए । इस तरह संसद ने अपने कामकाज के 156 घंटे बर्बाद किये । एक अनुमान के अनुसार इसके कारण जनता के 250 करोड़ स्वाह हो गए । मैं 250 करोड़ रुपये को ज्यादा अहमियत नहीं देता क्योंकि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में 250 करोड़ की ज्यादा अहमियत नहीं है लेकिन इन 250 करोड़ रुपयों से बहुत कुछ हो सकता था ।

सवाल उठता है कि क्या जनता सांसदों को इसलिए चुनकर भेजती है कि वो संसद में खड़े होकर तमाशा करें । क्या जनता सांसदों को संसद में हंगामा करने भेजती है । जवाब है कि जनता ये काम करने के लिए सांसदों को नहीं चुनती है बल्कि अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजती है ताकि वो उसकी समस्याओं का समाधान कर सके । जब नेता चुनाव प्रचार करते हैं तो कोई नहीं कहता कि मैं संसद में हंगामा करूंगा । जैसे मेरा नेता कहेगा, मैं वैसे शोर मचाऊँगा । मतलब साफ है कि सांसद वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए जनता ने उन्हें चुनकर संसद में बिठाया है । अपने नेता के इशारे पर हंगामा करके वो पार्टी का काम तो कर रहे हैं लेकिन जिस जनता ने उन्हें संसद में पहुंचाया है, उसके साथ धोखा कर रहे हैं । जनता के साथ धोखा करना लोकतंत्र का मजाक बनाना है और यह मजाक पिछले कई सालों से चल रहा है । यूपीए शासन के दौरान भाजपा ने भी यही काम किया था और भाजपा के शासन के दौरान विपक्ष भी यही काम कर रहा है ।

मनुष्य में देवत्व की प्रतिष्ठा करती है क्षमा भावना

-संदीप सृजन

भारत की गौरवशाली वांग्मय परम्परा के प्रमुख दर्शन जैन दर्शन और वैदिक दर्शन, दोनों ही भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के प्रमुख स्तंभ हैं, जो क्षमा को आत्म-उन्नति का माध्यम मानते हैं। जैन दर्शन में क्षमा अहिंसा का अभिन्न अंग है, जबकि वैदिक दर्शन में यह धर्म और मोक्ष का आधार है। क्षमा भावना मनुष्य में देवत्व का प्रतिष्ठा करती है यह कथन मानव जीवन की गहन सत्यता को उजागर करता है। क्षमा, जो क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध की जंजीरों से मुक्त करती है, मनुष्य को उसकी आंतरिक दिव्यता की ओर ले जाती है। क्षमा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक है। जैन और वैदिक ग्रंथों में क्षमा को आत्म-शुद्धि का साधन माना गया है। जैन दर्शन में यह कर्म-बंधन से मुक्ति का मार्ग है, जबकि वैदिक परंपरा में यह ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम।

जैन दर्शन, जो अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद पर आधारित है। क्षमा यहां अहिंसा का विस्तार है। जैन ग्रंथों जैसे 'उत्तराध्ययन सूत्र' और 'तत्वार्थ सूत्र' में क्षमा को 'क्षांति' कहा गया है, क्षांति का अर्थ है सहनशीलता और क्षमा। जैन मतानुसार, मनुष्य का जीवन कर्मों से बंधा है। क्रोध और द्वेष जैसे विकार नए कर्मों को आकर्षित करते हैं, जो आत्मा को जन्म-मरण के चक्र में बांधते हैं। क्षमा इन विकारों को नष्ट करती है, और आत्मा को कैवल्य (मोक्ष) की ओर ले जाती है।

जैन दर्शन में क्षमा को 'सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र' के त्रिरत्नों के अंतर्गत रखा गया है। उदाहरणस्वरूप, महावीर स्वामी ने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे, लेकिन कभी प्रतिशोध नहीं लिया। जब एक सर्प ने उन्हें डसा, तो उन्होंने क्षमा भाव से कहा, ₹यह इसका कर्म है।₹ यह घटना दर्शाती है कि क्षमा मनुष्य को देवत्व प्रदान करती है, क्योंकि देवता क्रोध से मुक्त होते हैं। जैन साहित्य में 'प्रतिक्रमण' अनुष्ठान है, जिसमें व्यक्ति अपने पापों के लिए क्षमा मांगता है। यह अनुष्ठान आत्म-शुद्धि का माध्यम है। जैन दर्शन क्षमा को चार प्रकारों में वर्गीकृत करता हैः क्रोध न करना, क्रोध होने पर उसे नियंत्रित करना, अपराधी को क्षमा करना, और स्वयं को क्षमा करना। 'आचारांग सूत्र' में वर्णित है कि क्षमा से जीव अहिंसा का पालन करता है, जो सभी जीवों के प्रति समानता का भाव जगाता है।

क्षमा जैन दर्शन में सामाजिक सद्भाव का भी साधन है। जैन समाज में क्षमा के माध्यम से संघर्षों का समाधान किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैन मुनि कभी विवाद में नहीं पड़ते; वे क्षमा भाव अपनाते हैं। यह दर्शन बताता है कि मनुष्य जन्म से देव नहीं होता, लेकिन क्षमा जैसे गुणों से देवत्व अर्जित कर सकता है। जैन दर्शन की यह शिक्षा आज के संघर्षपूर्ण विश्व में प्रासंगिक है, जहां क्षमा शांति का मार्ग प्रशस्त करती है।

वैदिक दर्शन, जो वेदों, उपनिषदों, पुराणों और स्मृतियों पर आधारित है, क्षमा को 'क्षमा' या 'तितिक्षा' के रूप में वर्णित करता है। ऋग्वेद में कहा गया हैः ₹क्षमां भूमिः क्षमां जलं, क्षमां वायुः क्षमां आकाशं₹ अर्थात क्षमा पृथ्वी, जल, वायु और आकाश की तरह अनंत है। वैदिक मतानुसार, मनुष्य ब्रह्म का अंश है, लेकिन माया और अविद्या से ढका हुआ। क्षमा इन आवरणों को हटाती है, और आत्मा को ब्रह्म से एकाकार करती है, जो देवत्व है।

वैदिक दर्शन में क्षमा को धर्म का अभिन्न भाग माना गया है। मनुस्मृति में लिखा हैः ₹क्षमा धर्म का मूल है।₹ क्षमा से मनुष्य अपने विकारों पर विजय प्राप्त करता है, और देवत्व की ओर बढ़ता है। उपनिषदों में, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में, क्षमा को 'तप' का रूप कहा गया है। वैदिक दर्शन में क्षमा 'कर्म योग' का भाग है, जहां कर्म फल की अपेक्षा न करके क्षमा की जाती है। यह भावना मनुष्य को उसके अहंकार से मुक्त करती है, और ब्रह्म-ज्ञान प्रदान करती है।

जैन और वैदिक दर्शन दोनों ही क्षमा को आत्म-उन्नति का साधन मानते हैं, दोनों दर्शन क्षमा को विकार-नाशक मानते हैं। जैन के 'क्षांति' और वैदिक के 'तितिक्षा' समान हैं। दोनों में क्षमा मोक्ष का मार्ग है। क्षमा भावना मनुष्य में देवत्व की प्रतिष्ठा करती है, जैसा जैन और वैदिक दर्शन सिखाते हैं। जैन में यह अहिंसा का फल है, वैदिक में धर्म का। दोनों से प्रेरणा लेकर, हम क्षमा अपनाकर दिव्य जीवन जी सकते हैं। क्षमा से ही विश्व शांति संभव है। अंत में, क्षमा अपनाएं, देवत्व प्राप्त करें।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार और स्तम्भकार हैं)

वर्षा ऋतु जीवन को स्फूर्णा देता है

विजय गर्ग

मनुष्य भौतिक लिप्साओं और आपाधापी की जिंदगी में प्रकृति में हो रहे सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस नहीं करता। साथ ही बदलते मौसम चक्र के हमारे शरीर में पड़ने वाले प्रभावों और बदलावों को भी हम अनदेखा करते हैं। दरअसल, हमारे जीवन में कृत्रिमता के गहरे हस्तक्षेप ने हमें प्रकृति के सुखमय प्रभाव के अहसास से वंचित कर दिया है। वातानुकूलित कमरों में बैठकर हम अहसास ही नहीं करते कि प्रकृति कैसे रूप-रंग बदल रही है।

अब यदि हम वर्षा ऋतु को ही देखें तो यह हमारे परिवेश ही नहीं हमारे शरीर में भी बदलाव करती है। कभी आपने बारिश के इस मौसम में अपनी एड़ी, तलवे या त्वचा की चमक को महसूस किया है! गर्मी और सर्दी में बहुत हद तक फट चुकी एड़ियां तथा शुष्क हो गई त्वचा, इस मौसम में पुनः खिल जाती है। यह, वह समय होता है जब 'जीवन' तेजी से अभिव्यक्त हो रहा होता है। विडंबना यह है कि हम इस बदलाव की अनदेखी करके इस सुख से वंचित हो जाते हैं।

यह मौसम, जीवन को स्फूर्णा देता है। जंगल, जमीन और प्रकृति में नवजीवन का संचार होता दिखाई देता है। इन महीनों के वातावरण में जीवनदाई शक्ति अपने चरमोत्कर्ष में उपलब्ध होती है। हवा की नमी, धूप-छांव का समन्वय, ऊर्जाओं की व्यापकता आदि तमाम जीवनदाई

घटक, सहजता से क्रियान्वित हो जाते हैं। इस कालखंड में, प्रकृति में बह रहा जीवन सक्रिय होकर प्रचुरता से अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है।

यह मौसम हमारे भीतर बह रही जीवनीशक्ति को संजोने और उसे रिचार्ज करने का है। प्रकृति और इस वातावरण को जी भर कर पीने से यह कार्य आसानी से संभव हो जाता है। इस वक्त प्रचुरता में सुलभ जीवनदाई ऊर्जा का उपयोग करके, शरीर अपने भीतर के ह्रास की मरम्मत स्वतः कर लेता है।

सुबह-सुबह, बादलों से आच्छादित आकाश के नीचे मैट बिछाकर लेट जाइए। आधे घंटे जी भर कर सांस लीजिए। लंबी सांस! लीजिए, कुछ रोकिए और छोड़िए। वातावरण की नमी को पीजिए। सांस के साथ उस नमी को भीतर महसूस कीजिए। रीढ़ की हड्डी में आती-जाती सांस का अनुभव कीजिए। उस गहरी सांस के साथ रीढ़ की हड्डी के फूलने और सिकुड़ने पर कुछ केंद्रित हो जाइए। शरीर को जितना हो सके स्ट्रेच कीजिए। आकाश को छूने के लिए स्वयं को फैलाइए। हड्डियों पर थोड़ा जोर डालिए। उन केंद्रों पर ध्यान लगाइए, जहां अक्सर दर्द रहता है। मसलन, घुटने, कमर आदि। इस मौसम में किया गया यह प्रयोग जीवन को निश्चित रूप से स्फूर्णा देगा। बस, विचारों के मध्य यांत्रिक रूप से नहीं करना है। करने में केंद्रित होना है।

निस्संदेह, इन महीनों में सहज उपलब्ध व्यापक ऊर्जा का, अपने भीतर की जीवन ऊर्जा से, मनुष्य यदि सही सही समन्वय बिठाना सीख ले, तो न सिर्फ शारीरिक स्तर के आयाम, अपितु मानसिक और आध्यात्मिक आयामों का भी संवर्धन संभव है। इस संवर्धन से प्राण शक्ति के घनत्व का ऐसा पुनर्भरण हो सकता है, जो न सिर्फ शरीर में व्याप्त गंभीर रोगों की संभावना को क्षीण करने की क्षमता प्रदान कर सकता है, बल्कि जीवन चलाने वाले मुख्य अंगों का लंबे समय तक ह्रास होने से रोक सकता है। इस विधा से व्यक्ति अपने भीतर की कार्यप्रणाली को इतना दुरुस्त रख सकता है कि वह लंबे समय तक रोगमुक्त, शक्ति संपन्न और दीर्घायु को प्राप्त हो सकता है। इन तकनीकों के जानकार, कई ऋषि-मुनियों के किस्से प्रचलित हैं, जो दो-पांच सौ वर्षों तक युवावान रहते थे।

विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

सीमा पार से हथियारों की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़; 5 ग्लॉक पिस्तौल सहित एक व्यक्ति गिरफ्तार

जांच अनुसार पाकिस्तान आधारित तस्कर राज्य की शांति और सद्भावना को भंग करने के लिए भेज रहे थे हथियारों की खेप : डीजीपी गौरव यादव

आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियाँ और बरामदगियाँ होने की उम्मीद : सीपी अमृतसर गुरप्रीत भुल्लर *

अमृतसर (साहिल बेरी)

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए जारी अभियान के दौरान अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक आरोपी को पाँच अति-आधुनिक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल और चार मैगज़ीन सहित गिरफ्तार कर सीमा पार से हथियारों की तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी आज यहाँ पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान अमित सिंह के रूप में हुई है, जो अमृतसर के गुरु की वडाली, छेहरटा का निवासी है। हथियार बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने उसका काले रंग का हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया है, जिसका प्रयोग वह खेप पहुँचाने के लिए करता था।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी अपने साथी गुरप्रीत सिंह उर्फ़ गिन्नी के माध्यम से पाकिस्तान आधारित तस्करों के संपर्क में था, जो राज्य में शांति और सद्भावना को भंग करने के लिए हथियारों की खेप भेजते थे।

डीजीपी ने कहा कि इस गिरफ्तारी और बरामदगी ने हथियारों की तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करने और क्षेत्र में एक बड़े अपराध को टालने में मदद की है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियाँ और बरामदगियाँ होने की उम्मीद है।

पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि भरोसेमंद जानकारी पर कार्रवाई करते हुए डीसीपी डिटेक्टिव रविंदरपाल सिंह, एडीसीपी-2 हरपाल सिंह और एसीपी पश्चिमी शिवदर्शन सिंह की निगरानी में थाना छैहरटा की पुलिस टीम ने गुप्त कार्रवाई करते हुए संदिग्ध अमित सिंह को उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वह किसी को हथियारों की खेप पहुँचाने जा रहा था।

सीपी ने आगे कहा कि जांच अनुसार गिरफ्तार आरोपी सीमा पार से अपने संचालकों द्वारा बताए गए स्थानों से ड्रोन के माध्यम से गिराई गई हथियारों की खेप प्राप्त करता था।

उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है और साथ ही उस व्यक्ति की पहचान की कोशिश भी जारी है, जिसे आरोपी खेप पहुँचाने जा रहा था।

इस संबंध में अमृतसर के थाना क्षेहरटा में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर नंबर 165 दिनांक 24.08.2025 दर्ज की गई है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल हेतु "दीक्षा" प्रशिक्षण का आयोजन

अमृतसर, (साहिल बेरी)

पंजाब सरकार के आदेशानुसार, सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कौर ने ज़िला परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. नीलम भगत के नेतृत्व में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, गर्भवती माताओं की विशेष देखभाल और प्रसूति एवं स्त्री रोग सेवाओं हेतु "दीक्षा" प्रशिक्षण का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण में, ज़िले भर के सभी ब्लॉकों में कार्यरत उन स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षण दिया गया, जो स्त्री एवं प्रसूति रोग सेवाओं से जुड़ी हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. चिंकी ठकुराल ने सभी स्टाफ को उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था और प्रसव की जटिलताओं के बारे में बहुत ही उचित तरीके से विशेष प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर, ज़िला परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. नीलम भगत ने कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर को कम करना और स्टाफ को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करना है ताकि प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके। इस अवसर पर ज़िला एम.ई.आई.ओ. अमरदीप सिंह, प्रशिक्षण समन्वयक कमलदीप भल्ला, रसपाल सिंह सहित समस्त स्टाफ उपस्थित था।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा "नेत्रदान-महादान" पखवाड़ा आरंभ

अमृतसर, (साहिल बेरी)

पंजाब सरकार के आदेशानुसार, सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कौर द्वारा सहायक सिविल सर्जन-सह-नोडल अधिकारी (एनटीसीबी) डॉ. राजिंदर पाल कौर के नेतृत्व में २५ अगस्त से ८ सितंबर तक नेत्रदान-महादान पखवाड़ा आरंभ किया गया है। इसी कड़ी में, सिविल सर्जन कार्यालय, अमृतसर में सभी नेत्र रोग अधिकारियों और समस्त कर्मचारियों द्वारा नेत्रदान की शपथ ली गई। इसमें सभी कर्मचारियों ने नेत्रदान की शपथ ली और सहमति पत्र भरे। इस अवसर पर जानकारी देते हुए सिविल सर्जन अमृतसर डॉ. किरणदीप कौर ने कहा कि नेत्रदान महादान है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति अपनी आँखें दान करता है, तो उसकी आँखों से दूसरा व्यक्ति अंधकार से बाहर निकलकर प्रकाश में अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। विश्व में लगभग १२ लाख लोग नेत्र रोगों के शिकार हैं, जिनमें से लगभग ३ लाख लोग बिना आँखों के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने अपील की कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नेत्रदान के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर ज़िला एम.ई.आई.ओ. अमरदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना अर्थात दुर्घटना या किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर, मृत्यु के बाद यथाशीघ्र या न्यूनतम ६ घंटे और अधिकतम २४ घंटे के भीतर नेत्रदान किया जा सकता है। इस पखवाड़े के दौरान ज़िले भर के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आम जनता को नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अवसर पर यूनाइटेड वे ऑफ ट्रस्ट एनजीओ द्वारा वार ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर मशीनें दान की गईं। इस अवसर पर संदीप कुमार ज्ञानी सहित सभी नेत्र रोग अधिकारी उपस्थित थे।

हेमन्त सोरेन का कोयला राज्यमंत्री के साथ की उच्च स्तरीय बैठक

पर्यावरण अनुकूल तथा पुनर्वास मुकम्मल ,खनन संपन्न हो जाने के उपरांत जमीन को रैयत को वापस लौटाया जाय

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कोयला खनन गतिविधियों, पर्यावरणीय संतुलन, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड के हितों, खनन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की भागीदारी, रोजगार सृजन, पर्यावरणीय संतुलन तथा राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व से संबंधित विषयों को प्रमुखता से रखा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा की खनन कार्य संपन्न हो जाने के उपरांत जमीन को भारत सरकार राज्य सरकार को वापस करे, ताकि उस जमीन को मूल रैयतों को लौटाया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के पुनर्वास, रोजगार, पर्यावरणीय संतुलन तथा आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता दी जाए।मौके पर केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि राज्य और केंद्र मिलकर समाधान तलाशेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि झारखंड के विकास और लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करेगी।

इस बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, खान सचिव अरवा राजकमल, खान निदेशक राहुल सिन्हा, सीएमपीडीआई के सीएमडी मनोज कुमार, बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता, सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह एवं बीसीसीएल के डीटी में एम. के अग्रवाल मौजूद थे।

आज से हमारा शासन चालू होगा , इसी में कोई अध्यक्ष या सचिव नहीं होगा

मनोरंजन सासमल , वरिष्ठ पत्रकार

भुबनेश्वर: क्या राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाएँ लोगों को ठीक से मिल रही हैं या नहीं? क्या लोगों को पुलिस थानों, अस्पतालों, तहसीलों आदि में जाने पर सभी सुविधाएँ मिल रही हैं? क्या उन्हें सुभद्रा योजना के तहत पैसे मिल रहे हैं? धान बेचते समय बाज़ार में क्या समस्याएँ आईं? अंत्योदय गृह योजना के तहत घर की किश्तें भरने के लिए किसने रिश्वत ली? क्या उन्हें भत्ते के पैसे मिल रहे हैं?सरकार अपनी प्रमुख सेवाओं और योजनाओं पर लोगों से फीडबैक लेगी। अगर कोई अधिकारी लोगों को सेवाएँ देने में विफल पाया गया, दुर्व्यवहार किया या रिश्वत ली, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार 'आम आदमी' प्रणाली शुरू करने जा रही है।

यह 'आम आदमी' प्रणाली उसी तरह लागू की जाएगी जैसे बीजद सरकार के दौरान '5-मेरी सरकार' लागू की गई थी। हालाँकि, इसमें 5 अध्यक्ष या सचिव नहीं होंगे। आने वाली शिकायतों और सुझावों की सीधे मुख्यमंत्री और प्रशासन सुनवाई करेगा। इसमें लगभग 20 विभागों की 150 से अधिक सेवाएँ उपलब्ध होंगी। अब 8 विभागों की 16 सेवाएँ उपलब्ध होंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार द्वारा लोगों को एक रिकॉर्डेड कॉल की जाएगी; इसमें उनसे विभिन्न प्रश्न पूछे जाएँगे। उदाहरण के लिए, जिस सरकारी कार्यालय में वे पहले गए थे, वहाँ उन्हें क्या सेवाएँ मिलीं, क्या वे उससे संतुष्ट थे, यदि संतुष्ट नहीं थे तो क्यों नहीं, सरकार को कौन सी सेवाएँ और प्रदान करनी चाहिए और किन क्षेत्रों में सुधार करना चाहिए। इससे एक तो लोगों की शिकायतों के आधार पर सेवाएँ न देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी, दूसरा, सरकार प्रस्तावों के आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी और आगामी योजनाओं के लिए नीति तय करेगी।

लोगों से फीडबैक लेने और उन्हें कॉल करके फीडबैक व शिकायत देने के लिए एक समर्पित कॉल सेंटर होगा। लोग टोल-फ्री नंबर 14471 पर कॉल कर सकते हैं। यह सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। वे व्हाट्सएप पर चैट और फीडबैक भी दे सकते हैं। इसके लिए 7400221903 नंबर जारी किया जाएगा। आप #FeedbackOdisha के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स-रे जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया पोस्ट कर सकते हैं। आप आम आदमी वेबसाइट पर चैटबॉट के माध्यम से भी चैट कर सकते हैं और ईमेल के माध्यम से भी फीडबैक दे सकते हैं।

मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 'आम आदमी' प्रणाली का शुभारंभ करने वाले हैं।

झारखंड विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पोल खोल चुका है भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामे की

पथ निर्माण विभाग मे भ्रष्टाचार का शिकार दामोदर नदी पुल ही नहीं खरसावां का संजय पुल भी यहां आदेश देना पड़ता है स्वयं हाईकोर्ट को

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

सरायकेला , झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सदन में पेश हुई सीएजी रिपोर्ट ने सरकार के कई विभागों की गंभीर लापरवाहियां और गड़बड़ियां उजागर कर दीं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुपालन प्रतिवेदन में साफ कहा गया है कि करोड़ों रुपए की लागत से ली गई कई योजनाओं का आम जनता को कोई लाभ नहीं मिला।

रिपोर्ट के मुताबिक, पथ निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण की एक योजना पर 19.15 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन कार्यपालक अभियंता और भू-अर्जन पदाधिकारी के बीच समन्वय की कमी से रकम बर्बाद हो गई।

इसी विभाग ने दामोदर और गवई नदी पर दो पुलों के लिए 15.09 करोड़ रुपए खर्च किए। पुल तो बन गए, लेकिन पहुंच पथ का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि जमीन अधिग्रहण ही नहीं किया गया। नतीजा यह कि इस पुल का कोई उपयोग नहीं हो पाया।

सीएजी ने बोकारो के चंदनकियारी प्रखंड में ग्रामीण विकास विभाग की एक योजना में 5.09 करोड़ रुपए की बर्बादी पकड़ी। इस राशि से बनी मॉल जैसी इमारत आज तक इस्तेमाल ही नहीं हुई।

यही नहीं, विभाग ने वेब आधारित अकाउंट प्रबंधन प्रणाली पर 1.77 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन यह प्रणाली अब तक काम ही नहीं कर रही है।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने 2014 में 16 शीतगृह और छंटाई केंद्रों पर 3.67 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन, एक दशक गुजरने के बाद भी इनमें काम शुरू नहीं हुआ। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने जमशेदपुर के धालभूमगढ़ में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल 1.55 करोड़ रुपए खर्च कर बना दिया, पर तीन साल बाद भी बंद पड़ा है।

रिपोर्ट में कुल मिलाकर करीब 41.10 करोड़ की ऐसी योजनाओं की स्थिति उजागर की गई है, जिनसे आम जनता को कोई लाभ नहीं मिला।

मजे की बात सरायकेला खरसावां जिला पथ निर्माण विभाग का है। ओडिशा का दो पूर्व प्रिन्सली स्टेट सरायकेला-खरसावां के कार्यों में भयंकर लुट मची है। आज एक सहायक अभियंता के पास 200से 300 करोड़ का काम लटका हुआ है, देखने बाला नदारद । सरकारी विभाग ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के मकड़े जाल में गिरफ्त में है । चहेते इंजिनियर ठेकेदारों की मिलि जूली सरकारी रिश्ता के कारण ऐसा कुछ नजारा है इस विभाग का यहां । मामला जमीन अधिग्रहण के ऊपर ढकेल दी जाती है । इन दो पूर्व देशी रियासत मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर में संजय नदी पर एक पुल अधुरा इसलिए रह गया कारण उसकी आधी पहुंच पथ अधिग्रहित हुई ही नहीं थी ,तो फिर उस प्राक्कलन को स्वीकृति मिली कैसे ? जिसपर एक जनहित याचिका के बाद स्वयं झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर बन अब रहा १ * वर्ष बाद उस अधुरा पुल । आज जहां अनेक विभागो को जिले को यहां भ्रष्ट अभियंता चलाते आये है । दरअसल रांची से बैठा सिंडिकेट का मोहरे है स्थानीय अभियंत्रण संस्थान ।

विधानसभा में रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है. कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार और मौजूदा गठबंधन दोनों ने ही जनता के हितों की अनदेखी की है. विपक्षी दलों का कहना है कि रिपोर्ट साफ दर्शाती है कि राज्य में योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कागजों पर हुआ. उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट के बाद सरकार को तत्काल दोषी अफसरों पर कार्रवाई करनी होगी. यह जनता के धन का खुला दुरुपयोग है.

ढेंकनाल के बिरसोला में बनेगा विश्वस्तरीय विमान प्रशिक्षण केंद्र

मनोरंजन सासमल , वरिष्ठ पत्रकार

भुबनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर में आयोजित पूर्वी नागरिक उड्डयन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार की प्रमुख पहल बी-मान (विमानन परिसंपत्तियों और नेटवर्क का निर्माण एवं प्रबंधन) के तहत एक कैडेट पायलट कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसमें आदिवासी लड़कियों को पायलट बनने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर, राज्य सरकार ने आज देश की अग्रणी विमान एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) सेवा प्रदाता, एयर वर्क्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार, भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आधुनिक एमआरओ सुविधा स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु एयर वर्क्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरी में एक विश्वस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है और यह हवाई अड्डा दुनिया भर के करोड़ों जगन्नाथ भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रवेश द्वार होगा। इसके साथ ही, झारसुगुड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए ज़मीन की व्यवस्था कर ली गई है। नई सरकार के गठन के बाद पिछले 14 महीनों में, ओडिशा के हवाई अड्डों को 15 नए गंतव्यों से जोड़ा गया है। हमारी यह नीति ओडिशा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन नेटवर्क से जोड़ने में सफल रही है। इसी कड़ी में, हम ओडिशा को आगे बढ़ाने के लिए भूमिका निर्माण और कौशल विकास पर भी ज़ोर दे रहे हैं और ढेंकनाल ज़िले के बिरसोला में एक विश्वस्तरीय विमानन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि उड़ान योजना जैसी परिवर्तनकारी पहल ने हमें प्रेरित किया है, जिसने वास्तव में विमानन का लोकतंत्रीकरण किया है और पूर्वी भारत के लिए नए क्षितिज खोले हैं। विमानन केवल हवाई अड्डों और उड़ानों तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे लोगों के सपनों को अवसरों से जोड़ने, हमारी अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने का एक अनूठा प्रयास है। 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के लिए हमारे प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयास हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। हम सब मिलकर ओडिशा की कनेक्टिविटी को मज़बूत करने और अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

कार्यक्रम में, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सपने को पूरी तरह साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि हवाई चप्पल पहनने वालों को भी अब उड़ान भरने का मौका मिलेगा। किंजरापु ने वादा किया कि ओडिशा के विमानन बुनियादी ढांचे के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहल, वाणिज्य एवं परिवहन राज्य मंत्री विभूति भूषण जेना और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओम प्रकाश चौधरी ने इस अवसर पर मुख्य भाषण दिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा ने स्वागत भाषण दिया, जबकि वाणिज्य एवं परिवहन विभाग की प्रमुख सचिव उषा पाधी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और धन्यवाद ज्ञापन किया।

मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर झारखंड विधानसभा गरम

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची , मतदाता गहन पुनरीक्षण झारखंड में लेकर राजनीति गरमा गई है. मंगलवार को झारखंड विधानसभा में इसके विरोध में एक प्रस्ताव पेश किया गया. जिसको लेकर विपक्ष ने विरोध जताया .

संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में यह प्रस्ताव पेश किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता पुनरीक्षण का मकसद केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ परामर्श के बाद वो इंडिया गठबंधन की तरफ से निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश कर रहे हैं. मंत्री ने आरोप लगाया कि मतदाता गहन पुनरिक्षण संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने और गरीबों एवं दलितों को वंचित करने की कोशिश है.

इस दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी इस तरह के प्रस्ताव का विरोध करेगी. उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को मतदाता बनाने की साजिश है और बीजेपी इसका विरोध करेगी. कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो से प्रस्ताव को मतदान के लिए रखने का आग्रह किया. अध्यक्ष ने उनका जवाब देते हुए कहा प्रस्ताव स्वतः ही पारित हो गया है क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास सदन में बहुमत है.इधर विधानसभा में सुबह से ही हंगामा देखने को मिला. दोनों पक्षों के विधायक प्रदर्शन करने के लिए सदन के बीचों बीच आ गए. हंगामे के कारण अध्यक्ष महतो को सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी. उन्होंने पहले 12 बजे तक और फिर दो बजे तक कार्यवाही स्थगित की थी.

सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने एस आई आर का मुद्दा उठाया. इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी एस आई आर के जरिए हमारे वोट चुराना चाहते हैं. हम एस आई आर का विरोध करते हैं और इसे वापस लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि हम अपने वोटों की चोरी नहीं होने दे सकते. इसके बाद सत्ता पक्ष के सदस्य वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा लगाते हुए आसन के समक्ष आ गए. वहीं बाद में बीजेपी विधायक भी आसन के सामने आ गए औ सूर्या हंसदा 'मुठभेड़' मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग करने लगे।

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल ने दिलाई शपथ

सेवानिवृत्त न्यायाधीश बने अध्यक्ष

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड

रांची , राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज राज भवन के दरबार हॉल में आयोजित विशेष समारोह में नवनीत कुमार (झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश) को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार एवं माननीय मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शपथ ग्रहण के उपरांत झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उक्त अवसर पर अन्य वरीय अधिकारीगण एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023